सूर्योदय 6:40 सूर्यास्त 5:29

आज का तापमान

शिमला	11.0 न्यू	21.0 अधि
धर्मशाला	12.5 न्यू	24.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	79,310
निफ्टी	24,537

सोना 1,44, 000 चांदी 1,86,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 21 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 191, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

दिल्ली के चावड़ी बाजार में इमारत गिरी, दो की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। हादसे के समय इमारत में 10 से 15 मजदूर मौजूद थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और हादसे की जांच के आदेश दिए। उन्होंने संबंधित जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित करने तथा ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। घायलों के बेहतर उपचार और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने को भी कहा। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस के अनुसार, स्लैब डालते समय इमारत ढह गई।

गोवा : पांच लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आदेश

एजेंसी, पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए एक परिवार के पांच सदस्यों के नाम दोबारा जोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वीरवार को कहा कि एड्रेस की पुष्टि करने के बाद 10 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने ईसीआई की आदेश पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी। यह मामला गोवा के सालगांवकर परिवार से जुड़ा है। परिवार के सदस्यों ने पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भरा था, लेकिन इसके बावजूद एसआईआर में उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नाम हटाने और फॉर्म 8 के आवेदन खारिज करने को चुनौती दी थी।

भाजपा ने गोकुल डेयरी चुनाव में नियम बदले : राहुल गांधी

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी के चुनाव को लेकर भाजपा पर चुनाव के बाद नियम बदलकर बहुमत छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी बताया। राहुल गांधी ने वीरवार को एक्स पर लिखा- गोकुल में दूध डेयरी चलाने वालों ने भाजपा को हरा दिया, तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए। 4 डायरेक्टर टूंसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। गोकुल दूध डेयरी में 19 अक्तूबर को 25 निदेशक पदों के लिए चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस समर्थित पैनल को 13 और भाजपा नीत महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिलीं थीं।

हरदीप पुरी निर्विरोध चुने राज्यसभा सांसद

एजेंसी, भोपाल। मध्यप्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। उनके निर्वाचन के साथ प्रदेश में राज्यसभा का संख्या समीकरण बदल गया है। अब 11 सीटों में भाजपा के 9 और कांग्रेस के 2 सांसद हैं। पुरी के नामांकन में 100 से ज्यादा कमियां होने का दावा करते हुए कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। पत्नी के नाम, विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी आपत्तियां खारिज कर दीं।

जंतर-मंतर हिंसा मामले में जांच समिति को मिलीं कम शिकायतें : सुप्रीम कोर्ट

प्रदर्शनकारियों व पुलिस पर हमले के पर्याप्त सबूत नहीं, जांच कमेटी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित हाई पावर्ड इंक्वायरी कमिटी को प्रभावित लोगों की तरफ से बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पर्याप्त जानकारी और साक्ष्यों के अभाव के चलते समिति अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने समिति को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि जंतर-मंतर हिंसा से संबंधित सभी लंबित याचिकाएं, वीडियो फुटेज और शिकायतें सीधे



◆सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया एक माह का समय

जांच समिति को सौंपी जाएं, ताकि जांच को गति मिल सके। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से पीड़ितों को कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जमा सामग्री और कमेटी तक पहुंची सामग्री के बीच अंतर है। पीड़ितों की ओर से शिकायतकर्ता को बुलाने के लिए कमेटी से अनुरोध किया जा सकता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि कमेटी का गठन पुलिस अधिकारियों या उनके वरिष्ठों को कार्रवाई करने से नहीं रोकता। अगर उन्हें लगता है कि मौके पर तैनात किसी पुलिसकर्मी ने गलत काम किया है, तो वे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अपने पास मौजूद सभी संबंधित सामग्री कमेटी को भेजें।

इसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं, हलफनामों और वीडियो क्लिप की प्रतियां शामिल होंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों की ओर से भेजी गई सामग्री पर भी एचपीआईसी विचार करेगी।

हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी 24 घंटे की अवधि

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय-सीमा पुलिस हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी, न कि औपचारिक गिरफ्तारी से। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत हिरासत और गिरफ्तारी में कृत्रिम अंतर नहीं किया जा सकता। यह फैसला एनडीपीएस मामले में चार आरोपितों की अपील पर आया। न्यायालय ने पाया कि आरोपितों को गिरफ्तारी से पहले करीब 18 घंटे हिरासत में रखा गया, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यूजीसी के विवादित नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विवादित यूजीसी नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियम बनाते समय देश की युवा पीढ़ी और सभी छात्रों के हितों की रक्षा जरूरी है। दरअसल, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को चुनौती देते हुए याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नियमों की धारा 3(सी) में जातिगत भेदभाव की परिभाषा सीमित रखी गई है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ भेदभाव को ही शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के अमल पर रोक लगाते हुए नई कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था।

पैरा एथलीटों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा-

खिलाड़ियों ने पदकों के साथ देशवासियों का दिल भी जीता



एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित हालिया एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की।

यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित हुआ। पीएम के साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने पैरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें साथ ही अगला लक्ष्य भी बताया। पीएम ने कहा कि पैरा खिलाड़ियों को अभी से 2028 लॉस एंजिलिस पैरा ओलंपिक की तैयारी में जुटना होगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान पैरा एथलीटों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, मुझे आप सभी से मिलने का काफी इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों पहले मैंने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीटों से मुलाकात की थी और अब मैं आप जैसे ऊर्जावान एथलीटों से मिल रहा हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मेडल तो जीता ही है, लेकिन साथ ही करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीता है। आप लोगों ने फिर दिखा दिया है कि सबसे ऊंची उड़ान हौसलों से होती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने कहा, एक समय ऐसा था कि कुछ खेल में भागीदारी सिर्फ औपचारिकता होती थी। पैरा एशियन गेम्स में 2010 में भारत ने 14 पदक जीते थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ी 114 पदक के साथ आए हैं।

घुसपैठियों को पहले मतदाता सूची से बाहर करेंगे, फिर देश से : अमित शाह

एसआईआर के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार केंद्र सरकार

एजेंसी, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की मतदाता सूची व इस देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस तीन करोड़ घुसपैठियों को बचाने के लिए देशभर में रैलियां निकाल रही है।

अमित शाह वीरवार को करनाल में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती देते हैं, लेकिन देश के मुद्दों पर संसद में चर्चा करने से बचते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है,



लेकिन राहुल गांधी अपनी और अपने साथियों की यह गारंटी दें कि वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से भागेंगे नहीं। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए रैली करने वाली कांग्रेस 13 करोड़ वोट कटने का दावा करती है, जिसकी सच्चाई यह है कि 2.8 करोड़ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। सवा छह करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। देश में एक करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिनके तीन से ज्यादा स्थानों पर वोट थे। तीन करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो न तो चुनाव आयोग के सामने आ रहे हैं और न ही धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इन घुसैपठियों को पहले मतदाता सूची से बाहर करेगी और फिर देश से बाहर करेगी। हाथ में संविधान लेकर चलने वाले संसद की बात सड़क पर करते हैं। संवैधानिक संस्था का सबसे अधिक अपमान करते हैं।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास

एजेंसी, लिसबन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 41 साल के रोनाल्डो ने वीरवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवंबर के इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वह पुर्तगाल की नंबर-7 जर्सी टीम को लौटा देंगे। रोनाल्डो का सफर 20 अगस्त 2003 को कजाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ था। तब वह सिर्फ 18 साल के थे। अगले 23 साल में उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मैच खेले और सबसे ज्यादा 146 गोल किए। उनके नाम 46 असिस्ट भी दर्ज हैं। असिस्ट का मतलब है गोल करने वाले खिलाड़ी को आखिरी पास देना।



कांग्रेस राज में घोटाले पर घोटाले हुए : योगी

राहुल गांधी बार-बार फेल हो रहे, हारने पर कहते हैं ईवीएम खराब है

एजेंसी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वीरवार को 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले पर घोटाले हुए। आज यही कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है, जबकि 1975 में इसी पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था।

योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा उनकी स्थिति बार-बार फेल होने वाले उस लड़के जैसी हो गई है, जो हर बार अपनी नाकामी का नया बहाना बनाता है। चुनाव जीतने पर ये अपनी मेहनत का श्रेय लेते हैं और हारने पर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ खड़े रहे। सरकार ने वैक्सीन विकसित कराई और लोगों को मुफ्त राशन, इलाज और वैक्सीन उपलब्ध कराई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बताकर दुष्प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय एक कहावत प्रचलित थी- 'जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा है कोई कुख्यात गुंडा।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा- 'देख सपाई, बिटियां घबराई।' योगी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान बरेली, संभल, बुलंदशहर, मेरठ और सहारनपुर में दंगे हुए।

कांग्रेस के शासन में हुए 2जी व कोयला घोटाले



योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास खो दिया। उसके शासनकाल में 2जी और कोयला घोटाले हुए। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगी। 2014 से पहले देश में अराजकता, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार का माहौल था। आज भारत दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।

◆मोदी सरकार ने मुफ्त राशन, इलाज व वैक्सीन दी

◆ जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें कुख्यात गुंडा

यूजर्स की पोस्ट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे जिम्मेदार

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म करने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया नियमों में बदलाव पर चर्चा शुरू की है। इसके तहत यूजर्स की पोस्ट, वीडियो और कमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन कंपनियों को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिलती है। इसके तहत यूजर्स की पोस्ट और कमेंट के लिए कंपनियों को सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स की कानूनी सुरक्षा हटाने की तैयारी

सुरक्षा की वजह से बढ़ा मेटा-गूगल का कारोबार

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुरक्षा ने मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियों को यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर बड़े कारोबार खड़े करने में मदद की है। उन्हें हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट की कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। सरकार के एक वर्ग का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ जानकारी पहुंचाने वाले माध्यम नहीं हैं। वे एल्गोरिदम से कंटेंट की रैंकिंग, सिफारिश और पहुंच तय करते हैं। ये प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन के आधार पर पोस्ट हटाते या सीमित करते हैं। ये नियम कई बार भारतीय कानूनों से अलग हो सकते हैं।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष

परिवार की कमाई और सरकारी पद के दुरुपयोग की होगी पड़ताल

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हराकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बाद डेमोक्रेट्स अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की कोशिश हो रही है।

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक डेमोक्रेट्स आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने अपने पद का इस्तेमाल कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया और संपत्ति जुटाई। इससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि वे यह पता लगाएंगे राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप और उनके परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ी। उनका फोकस ट्रंप के बेटों और दामाद जेरेड कुशनर के कारोबारी सौदों पर है। हाउस में कुल 435 सीटें हैं। सभी सीटों पर चुनाव हुए। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 242 और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 151 सीटें जीती हैं। 42 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट्स को जरूरी बहुमत मिल चुका है।

हार के बाद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में बगावत



मिडटर्म चुनाव में हार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में अंदरूनी नाराजगी सामने आने लगी है। टेक्सास के रिपब्लिकन नेता चैड विलबैंक्स ने ईरान युद्ध, टैरिफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पक्ष लेने वाले ट्रंप के फैसलों को हार की वजह बताया। सीएनएन के मुताबिक, ट्रंप के करीबी नेताओं ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति को ईरान युद्ध में उलझा दिया, लेकिन इससे निकलने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई। वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि ईरान युद्ध के कारण डोनाल्ड ट्रंप के कई पुराने समर्थकों ने इस बार रिपब्लिकन पार्टी से दूरी बनाई। वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जुआरी बताया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे जुआरी हैं, जो हारने के बाद भी खेल छोड़ने को तैयार नहीं होता। वेंस के बॉस (ट्रंप) जंग का अगला दौर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वेंस को ये बातें अपने बॉस से कहनी चाहिए।

शेयर बाजार में दिवाली से पहले बहार सेंसेक्स 2009, निफ्टी 576 अंक उछला

एजेंसी, नई दिल्ली। धनतेरस से एक दिन पहले 5 नवंबर को सेंसेक्स 2009 अंक या 2.60% चढ़कर 79,310 पर बंद हुआ। इसे तेजी से निवेशकों की दौलत 8 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई।

निफ्टी में भी 576 अंक या 2.40% की तेजी रही, ये 24,537 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने 4 सितंबर के बाद पहली बार 24 हजार का आंकड़ा पार किया। ये इस साल की सेंसेक्स की दूसरी बड़ी बढ़त है। 8 अप्रैल को सेंसेक्स 2,946 अंक चढ़ा था। यानी करीब सेंसेक्स में 7 महीने बाद इतनी बड़ी तेजी आई है। मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी दोनों सदनों में हार गई। इससे ईरान जंग रुकने की उम्मीद बढ़ी है। जंग थमने पर कारोबार आसान होगा। इसलिए लोग बाजार में लौटे। नतीजों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी रही। ईरान जंग जल्द खत्म होने की संभावना से ब्रेंट क्रूड टूटकर 94 डॉलर और अमेरिकी WTI क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।



◆ सेंसेक्स में सात महीने की सबसे बड़ी तेजी निवेशकों की दौलत 8 लाख करोड़ बढ़ी

उत्तराखंड में परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 59 नई बसें, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवार को मुख्यमंत्री आवास से उत्तराखंड परिवहन निगम की 59 नई साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के निगम के बेड़े में शामिल होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सड़क संपर्क के साथ मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई बसों के संचालन से विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इससे



◆नैनीताल मंडल को 19, टनकपुर व देहरादून मंडल को 20-20 बसें आवंटित

स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटकों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। परिवहन निगम की इन 59 बसों में से नैनीताल मंडल को 19, टनकपुर मंडल को 20 और देहरादून मंडल को 20 बसें आवंटित की गई हैं। इनका संचालन जरूरत के अनुसार विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। वर्तमान में परिवहन निगम के बेड़े में कुल 1,276 बसें संचालित हैं। इनमें निगम की 891 और 385 अनुबंधित बसें शामिल हैं। बीएस-06 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नई बसों के शामिल होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम देहग्रां पहुंचे सीएम सुक्खू, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद; बैरागढ़ में सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा

जनजातीय क्षेत्रों में सोलर प्रोजेक्ट पर सरकार देगी 5% ब्याज सब्सिडी

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ स्थित देहग्रां पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां स्थानीय ग्रामीणों, महिला मंडलों और युवक मंडलों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना।

इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने बैरागढ़ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा की। इसके अलावा क्षेत्र की 182 पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का



उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की वास्तविक समस्याओं और भौगोलिक परिस्थितियों को समझना है। इससे सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करने और बजट में जरूरी बदलाव करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सुक्खू ने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को आजीविका के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित कर रही है। होम-स्टे स्थापित करने, विस्तार और उन्नयन के लिए पांच करोड़ रुपये तक के निवेश पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत निजी भूमि पर 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक के सोलर पैनल स्थापित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बैंक ऋण लेने वाले लाभार्थियों को नौ प्रतिशत ब्याज में से पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।

इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले माह से 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करेगी। इसके तहत गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही लाभार्थियों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली और स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं और मांग पत्र लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त सभी जायज शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। दुर्गम चुराह क्षेत्र के देहग्रां में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्थानीय लोगों, महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर, पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस महासचिव यशवंत खन्ना, हज कमेटी के चेयरमैन दिलदार अली भट्ट, कांग्रेस नेता प्रकाश बटाली, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपिंदर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

रोहित ठाकुर ने लोकार्पित किया 2.50 करोड़ का लोहट पुल

जुब्बल-नावर-कोटखाई में 850 करोड़ के विकास कार्यों से तेजी से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत बाग डुमेहर पंचायत में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित लोहट पुल का लोकार्पण किया। यह पुल पंचायत के लोगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग थी। इसका शिलान्यास भी शिक्षा मंत्री ने 15 फरवरी 2023 को किया था। पुल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पिछले चार वर्षों के कार्यकाल में जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र ने विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सुरक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विकास के मामले में एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

850 करोड़ रुपये से चल रहे विकास कार्य : शिक्षा मंत्री ने बताया कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क और भवन निर्माण पर वर्तमान में करीब 850 करोड़ रुपये खर्च किए जा



◆ कोटखाई में 45 करोड़ से बनेगा केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा सुविधा

रहे हैं। अब तक 30 अलग-अलग भवनों का निर्माण पूरा कर उन्हें जनता को समर्पित किया जा चुका है। आने वाले एक वर्ष में 20 अन्य निर्माणाधीन भवन भी जनता को सौंपे जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पांच पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि चार अन्य पुल निर्माणाधीन हैं। इन्हें भी जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक 205 नई सड़कों का निर्माण किया गया है और उनकी पासिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा भी नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है।

कोटखाई में 45 करोड़ से बनेगा केंद्रीय विद्यालय : रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को अपने घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

5.36 करोड़ से बन रहे बीडीओ कार्यालय भवन का निरीक्षण : इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विकास खंड अधिकारी कोटखाई के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया। करीब 5 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह पांच मंजिला भवन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। इसके निर्माण से विकास खंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास कार्यों के संचालन में भी आसानी होगी।

उन्होंने बताया कि भवन में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय और आवास के साथ कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरे बनाए जा रहे हैं। भवन के प्रथम तल पर पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें लिफ्ट और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

श्रमिकों को मिली 115 करोड़ की आर्थिक मदद

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से 51 हजार श्रमिकों को करीब 115 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसमें कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के 1047 पंजीकृत कामगार भी शामिल हैं। वह ग्राम पंचायत चमयाना के सामुदायिक भवन में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड शिमला वृत्त की ओर से आयोजित एक दिवसीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कामगार बोर्ड श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों का बोर्ड में पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र की नौ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा और विकास को गति मिलेगी।

बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने श्रमिकों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत शिक्षा सहायता, चिकित्सा सुविधा, मातृत्व एवं पितृत्व लाभ, विवाह सहायता, पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में अब तक 1047 श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें 106 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 27,72,600 रुपये तथा बच्चों के विवाह के लिए 2,04,000 रुपये की सहायता दी गई है।

15 नवंबर से ऑनलाइन होगी ई-गजट में नाम बदलने और संशोधन की प्रक्रिया

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में ई-गजट के माध्यम से नाम परिवर्तन और नाम में संशोधन करवाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होने जा रही है। प्रदेश के मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने इस संबंध में नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 नवंबर, 2026 से आवेदकों को नाम परिवर्तन और संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पहले यह सुविधा ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध थी। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब यह सेवा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। 15 नवंबर के बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में नाम परिवर्तन या नाम में संशोधन करवाने के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन जमा करवाना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। आवेदकों को आवेदन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही और पूरी हों।

पुजारली में भूमि अधिग्रहण प्रभावितों की 26 नवंबर को होगी जनसुनवाई

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) की योजना सब हेड-एल डब्ल्यूएसएस शिमला के तहत ग्राम पंचायत पुजारली में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर 26 नवंबर, 2026 को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जनसुनवाई सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत पुजारली में होगी। इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों, संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य इच्छुक लोगों को अपने विचार, सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

उपमंडलाधिकारी (नागरिक), शिमला ग्रामीण कार्तिकेय शर्मा द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों को समझना और प्रभावित लोगों की राय को प्रक्रिया में शामिल करना है।

जनसुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई (एसआईएयू) की ओर से तैयार सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोनों दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवार और अन्य संबंधित व्यक्ति इन्हें पढ़कर प्रस्तावित अधिग्रहण के संभावित प्रभावों को समझ सकें। इसके आधार पर वे अपनी आपत्तियां और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे।

प्रशासन ने प्रभावित परिवारों, पंचायत प्रतिनिधियों और सभी इच्छुक पक्षों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर पहुंचकर जनसुनवाई में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर उन्हें नियमानुसार अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्ति जनसुनवाई की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर अपनी लिखित आपत्तियां और सुझाव भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर शिक्षक संगठनों का कड़ा रुख

स्वायत्तता से छेड़छाड़ पर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे शिक्षक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर शिक्षाविदों, शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी छह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सुरेश भारद्वाज तथा विधायक एवं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रणधीर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ हुई तो शिक्षक समुदाय राजभवन तक पैदल मार्च करेगा।

◆ शिक्षाविदों ने विश्वविद्यालयों की अकादमिक गरिमा और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया सुरक्षित रखने की उठाई मांग

पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, शोध और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक नीतियां निर्धारित करने, शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाने और संस्थागत निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की स्वायत्तता का संरक्षण केवल शिक्षकों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में बाहरी हस्तक्षेप से उनकी अकादमिक पहचान और स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसलिए विश्वविद्यालयों की निर्णय लेने की व्यवस्था और शैक्षणिक गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है।

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की गरिमा की पहचान है। प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी अकादमिक परंपरा, विशिष्ट पहचान और निर्णय लेने की व्यवस्था होती है। इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, तभी शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकेंगे।

उन्होंने विश्वविद्यालय समुदाय की चिंताओं और सुझावों को गंभीरता से सुनने तथा सभी संबंधित पक्षों के बीच सार्थक संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संस्थापक कुलपति प्रो. देव दत्त शर्मा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. चंद्रमोहन परशीरा ने भी विचार रखे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गरिमा, स्वतंत्र पहचान और अकादमिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सहित प्रदेश के सभी छह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

नादौन में दिसंबर में जुटेंगे विद्युत बोर्ड के खिलाड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की 23वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और 48वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 दिसंबर, 2026 तक नादौन, जिला हमीरपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 दिसंबर को नादौन स्थित नवनिर्मित खेल स्टेडियम में प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. प्रबोध सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं और आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। बैठक में बोर्ड खेल संगठन के उपाध्यक्ष एवं निदेशक (तकनीकी) ई. मदन गोपाल शर्मा, महासचिव सहित अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से आयोजन स्थल पर खेल सुविधाओं, मैदानों की तैयारी, खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के ठहरने, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य आवश्यक प्रबंधों की प्रगति से अध्यक्ष को अवगत करवाया गया।

चिट्टा तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर शिमला पुलिस का बड़ा प्रहार



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के दो मामलों में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर चंडीगढ़ से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरोपियों के अंतरराज्यीय सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दोनों मामलों में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

पहले मामले में 11 अक्तूबर को शोघी चौकी के पास बस की तलाशी के दौरान भुवनेश चौहान और गुलशन ठाकुर से करीब 22 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जांच में चंडीगढ़ के साजन उर्फ सैम और विकास उर्फ आकाश के नाम सामने आए। पुलिस ने 27 अक्तूबर को दोनों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। जांच में विकास को मुख्य सप्लायर और साजन को मध्यस्थ पाया गया। दूसरे मामले में 27 सितंबर को शोघी के पास बस में सवार क्षितिज वर्मा से करीब छह ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पूछताछ में उसने चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी रोहित से नशा खरीदने की जानकारी दी। पुलिस ने चार अक्तूबर को रोहित को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेन-देन के विश्लेषण से सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिली। वर्ष 2026 में अब तक 93 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार और 68 अंतरराज्यीय नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं।

गुरु रविदास जयंती यात्रा की तैयारियों को लेकर आज होगी विशेष बैठक

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चलाए जा रहे 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत पंजाब से वाराणसी तक निकाली जाने वाली भव्य यात्रा की तैयारियों को लेकर आज 6 नवंबर को विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सोलन जिले के कुमारहट्टी स्थित होटल न्यू वैदिक में होगी। राज्यसभा सांसद, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के प्रदेश संयोजक डॉ. सिकंदर कुमार ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और यात्रा की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तिलक राज शर्मा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुमीत शर्मा और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पवन काजल भी बैठक में शामिल होंगे।

बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल, सोलन के जिलाध्यक्ष रतन सिंह पाल, सिरमौर के जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता सहित दोनों जिलों की



◆ गुरु रविदास जयंती यात्रा के स्वागत और आयोजन की आज कुमारहट्टी में बनेगी रणनीति

जिला एवं मंडल स्तर की अभियान टोलियां भी भाग लेंगी।

डॉ. सिकंदर कुमार ने बताया कि संत रविदास जी के सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह यात्रा पंजाब से शुरू होकर चंडीगढ़ के रास्ते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और आगे वाराणसी तक जाएगी। बैठक में यात्रा के स्वागत, विभिन्न पड़ावों और आयोजन से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

स्कूलों में सुरक्षित बचपन के लिए हिमाचल पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'स्कूल कनेक्ट' पहल शुरू की है। दो नवंबर को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पुलिस, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय शिमला में 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। पुलिस का प्रयास अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के साथ-साथ संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें रोकना भी है। बैठक में स्कूलों में सीसीटीवी निगरानी, आगंतुकों की जांच, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा पर चर्चा हुई। बच्चों को अपहरण, यौन शोषण और बुलिंग से बचाने के लिए जागरूकता तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। पुलिस ने अभिभावकों को निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के दौरान चालक का सत्यापन करवाने और स्कूल प्रबंधन को जानकारी देने की सलाह दी। शिमला में स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय यातायात पुलिस की तैनाती तथा आसपास गश्त भी सुनिश्चित की जा रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर सरकार का विशेष जोर : अनिरुद्ध सिंह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिक्षा बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। वह कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बलदेहां में राघव पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने वर्षभर शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई के अधीन लाया गया है और आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालयों को भी सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मंत्री ने स्कूल में पेयजल की कमी का संज्ञान लेते हुए जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता को जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।



◆ बलदेहां स्कूल में पेयजल संकट दूर करने के निर्देश भंडारण व्यवस्था के लिए 50 हजार रुपए देने की घोषणा

उन्होंने कहा कि बलदेहां, मशोबरा और शिमला के साथ लगती चार-पांच अन्य पंचायतों में पेयजल की समस्या दूर करने तथा छूटी हुई बस्तियों को पेयजल सुविधा से जोड़ने के लिए सुन्नी-शकरोली से शिमला शहर की उठाऊ पेयजल योजना के साथ लिंक किया जाएगा।

उन्होंने विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की। साथ ही स्कूल में पेयजल भंडारण की व्यवस्था करने के लिए प्रबंधन को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की। स्कूल की प्रधानाचार्य योगेश्वरी वर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्कूल की विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखीं। मंत्री ने स्कूल प्रबंधन और स्थानीय पंचायत प्रधान की मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया।

समारोह के दौरान मंत्री ने विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्री-नर्सरी में आरुशी वर्मा और पलवित प्रथम, वंश ठाकुर और समर कश्यप द्वितीय तथा शिवांशी तृतीय स्थान पर रहे। नर्सरी में हिमानी कश्यप प्रथम, जीविका द्वितीय और अवनि तृतीय रही। केजी में दीवाशी और वंशिका शर्मा प्रथम, लियांश ठाकुर द्वितीय तथा विहान ठाकुर और लक्षित तृतीय रहे। पहली कक्षा में ईशान ठाकुर प्रथम, रोहन द्वितीय और निशांत तृतीय रहे। दूसरी में मानवी प्रथम, अक्षत ठाकुर द्वितीय और दयारा कंवर तृतीय रहे। तीसरी में दित्या ठाकुर प्रथम, सानवी ठाकुर द्वितीय और नव्या तृतीय रही।

कोटखाई में कांग्रेस की मासिक बैठक, संगठन मजबूती पर विशेष जोर



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। होटल त्रिमूर्ति, गुम्मा (कोटखाई) में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई की संगठनात्मक मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर ने की। इस दौरान शिमला ग्रामीण संगठनात्मक जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर बुशहर के विधायक रहे स्वर्गीय नंद लाल के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित उपस्थित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्रदेश और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के साथ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा और पार्टी की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के विषय भी उठाए गए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, पूर्व अध्यक्ष मोती लाल डेरटा, विभिन्न जोन के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

जनभागीदारी युवाओं को नशे से बचाने के लिए सभी विभाग निभाएंगे जिम्मेदारी, जनभागीदारी से बनेगा स्वस्थ हिमाचल

तम्बाकू मुक्त हिमाचल के लिए 60 दिवसीय अभियान शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश को तम्बाकू मुक्त बनाने और युवा पीढ़ी को तम्बाकू एवं निकोटीन की लत से बचाने के लिए प्रदेशभर में 60 दिवसीय 'तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन-जागरूकता गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों, गांवों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में प्रत्येक विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ और शहरी निकायों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 अक्तूबर 2026 को इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरों और युवाओं को तम्बाकू एवं निकोटीन की लत से बचाना, तम्बाकू सेवन की शुरुआत रोकना तथा इसकी आदत छोड़ने के इच्छुक लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसे नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों से भी जोड़ा जाएगा।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के 60 दिनों के लिए गतिविधियों का रोस्टर तैयार किया जाए। प्रतिदिन एक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और प्रत्येक अधिकारी को गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। व्यापार मंडलों को भी अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा।

अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा मेडिकल संस्थानों में तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। परिसरों में तम्बाकू निषेध के सूचना पट्ट लगाए जाएंगे और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं सेवन पर रोक लागू होगी। शिक्षण संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में बिक्री रोकने के लिए विशेष निरीक्षण किए जाएंगे। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए निबंध, भाषण, पोस्टर, चित्रकला, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के साथ रैलियां भी आयोजित होंगी। तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए राज्य, जिला और खंड स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वॉड नियमित निरीक्षण करेंगे।



तम्बाकू मुक्त अभियान को लेकर बैठक करते उपायुक्त व अधिकारी

युवाओं की भागीदारी और व्यापक प्रचार पर जोर

अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। मैराथन, साइक्लोथॉन, जागरूकता रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों, छात्रावासों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तक भी जागरूकता गतिविधियां पहुंचाई जाएंगी। समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान का प्रचार किया जाएगा। तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को स्वास्थ्य विभाग के नशा मुक्ति केंद्रों से परामर्श और सहायता मिलेगी। इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-2356 पर संपर्क किया जा सकता है। अभियान का संदेश है-'तम्बाकू छोड़ो, जिंदगी चुनो।' उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने, नियमित निरीक्षण करने और गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित और ऑनलाइन जुड़े अधिकारियों को तम्बाकू से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में हिमाचल प्रदेश

न्यूज ब्रीफ

जीजीडीएसडी कॉलेज में दीपावली उत्सव की रही धूम



भारतेन्दु संवाददाता, राजपुर। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, राजपुर में हिंदी साहित्य परिषद समिति की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य पर रंगोली निर्माण एवं सजावट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के संस्थापक पंडित अमरनाथ शर्मा की प्रतिमा के समक्ष भी आकर्षक रंगोली बनाकर परिसर को सजाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य डॉ. विवेक शर्मा ने सभी विद्यार्थियों और महाविद्यालय परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने घर की तरह महाविद्यालय को सजाया है। हिंदी साहित्य परिषद के विद्यार्थियों ने सभी का आभार व्यक्त किया।

महाराणा प्रताप स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया दीपावली उत्सव



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दीपावली उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रंगारंग गतिविधियां आयोजित की गईं। किंडरगार्टन के नन्हे बच्चों ने कठपुतली नृत्य और दीपावली पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। चारों सदनों के बीच आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप हाउस ने प्रथम, एस. राधाकृष्णन हाउस ने द्वितीय तथा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हाउस ने तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुलदीप सिंह ठाकुर, प्रबंधक पी.एस. राणा और प्रधानाचार्या पूजा महाजन ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की तथा सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर महासंघ ने खोला मोर्चा, 13 नवंबर को सोलन में प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की अर्की इकाई की बैठक वीरवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में अध्यक्ष के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों और अन्य मांगों पर चर्चा की गई। इकाई के महासचिव अनिल शर्मा ने बताया कि संघर्ष समिति के निर्णयानुसार पांच सदस्य 13 नवंबर को सोलन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देंगे, जबकि 14 सदस्य 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन में भाग लेंगे। पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी पर रोष जताते हुए सरकार से सभी देय भुगतान शीघ्र जारी करने की मांग की। बैठक में जिला महासंघ के पदाधिकारी और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

बातल चौक पर रंगड़ों के छत्ते से दहशत

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की-कुनिहार सड़क मार्ग पर स्थित बातल चौक में रंगड़ों के छत्ते ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों, दुकानदारों और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को रंगड़ों के हमले का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार दो दिन पहले रंगड़ों ने एक दुकानदार को काट लिया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा। लोगों का कहना है कि चौक पर दिनभर आवाजाही रहती है और रंगड़ों का हमला किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से छत्ते को जल्द सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है। डीएफओ कुनिहार राज कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही छत्ता हटा दिया जाएगा।

सरकार हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध: संजय अवस्थी

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



संजय अवस्थी को वीरवार ग्राम पंचायत कशलोग के गांव नेवड़ी में भागीरथ शर्मा द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 1 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ करने के उपरान्त जन समूह को संबोधित कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग समय की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई है, जिसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ौतरी, प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली फसलों जैसे मक्की, गेंहू व हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों व पशुपालकों को उत्पादों के सही दाम मिल रहे है। उन्होंने महिला मंडल भवन नेवड़ी तथा गांव खाली में वर्षा शालिका के निर्माण के लिए संबंधित विभाग द्वारा तैयार किए गए प्राकलन के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गांव नेवड़ी के लिए 15 सोलर लाइटें उपलब्ध करवाने तथा महिला मंडल कशलोग और महिला मंडल नेवड़ी को 11-11 हजार रुपए देने की घोषणा भी की।

अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ऐतिहासिक और युवा हितैषी : पवन काजल

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक पवन काजल ने अग्निवीरों का सेवाकाल चार से छह वर्ष करने और स्थायी तैनाती के अवसर देने के केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक एवं युवा हितैषी बताया। भड़ियाड़ा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को दिवाली का तोहफा दिया है। इससे सेना में भर्ती के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। हिमाचल में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को 1500 रुपए का वार्षिक पास मिलने से ग्रामीणों को राहत मिली है। कच्छयारी-भंगवार फोरलेन पर अंडरपास और फुट ओवरब्रिज की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने का आह्वान किया और युवा क्लब को 11 हजार रुपए दिए। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में धर्मशाला यूथ स्टार ने फाइव स्टार क्लब शाहपुर को हराकर ट्रॉफी जीती।



परिवहन निगम के पेंशनरों ने उठाई 8 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला कांगड़ा की मासिक बैठक 5 नवंबर को आयोजित की गई। बैठक में मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रदेश सरकार से दिवाली से पहले 8 प्रतिशत महंगाई राहत जारी करने तथा पेंशन संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने की मांग उठाई गई। सदस्यों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलने चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।

जयराम ठाकुर सत्ता में हों या विपक्ष में हमेशा जनता के बीच रहे: राकेश वालिया

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश वालिया ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय जननेता हैं, जो सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा जनता के बीच रहे हैं।



उन्होंने कहा कि जयराम ने अपने राजनीतिक जीवन में जनता के सुख-दुख में शामिल होकर लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। राकेश वालिया ने कहा कि जयराम ठाकुर की लोकप्रियता व जनता के बीच उनकी सक्रियता से परेशान होकर कांग्रेस के कुछ नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं को मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बजाय अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। केवल बयान देने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद मंडी जिला के विकास कार्यों पर विराम क्यों लगा हुआ है? मंडी को स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों, रोजगार व नई विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां मिली हैं, इसका जवाब कांग्रेस नेताओं को जनता के सामने देना चाहिए। जयराम के सीएम कार्यकाल में मंडी जिला को विकास की दृष्टि से विशेष पहचान मिली थी। आज भी उनके कार्यकाल में शुरू हुई परियोजनाओं और विकास कार्यों की चर्चा होती है। विपक्ष के नेता के रूप में भी वह लगातार प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बजाय अपना कद देखकर बयानबाजी करें और मंडी की जनता के विकास का हिसाब दें।

बाहरा विश्वविद्यालय में 200 युवाओं ने सीखे स्वरोजगार के गुर

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। बाहरा विश्वविद्यालय वाकनाघाट में एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय सोलन की ओर से राष्ट्रीय उद्यमिता सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 विद्यार्थियों और उद्यमियों ने भाग लिया। 11 संस्थानों के विशेषज्ञों और दो सफल उद्यमियों ने स्टार्टअप, वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं और निर्यात संबंधी जानकारी दी। विश्वविद्यालय के चेयरमैन गुरविंदर सिंह बहरा ने युवाओं से नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। सिडबी, आरबीआई, पीएनबी और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने कारोबार शुरू करने के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। सफल उद्यमियों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

मंडी में केवल हरित पटाखे चलाने की अनुमति

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला मंडी में आगामी त्योहारों के दौरान केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि दीपावली पर 8 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य पटाखों का विक्रय और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, आत्मनिर्भर हिमाचल के दावे खोखले : राकेश जम्वाल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लैब जांच, दवाइयों और ऑपरेशन की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ऑपरेशन घटकर एक चौथाई रह जाना चिंताजनक है। हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के लंबित भुगतान से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने 108 एंबुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। जम्वाल ने सरकार से लंबित भुगतान जारी करने और स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल सुचारू बनाने की मांग की।

गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सोलन ने 20वां वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन का 20वां वार्षिक समारोह 'चरैवेति चरैवेति' थीम के तहत धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में 1 एचपी एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव थॉमस मुख्य अतिथि रहे। विद्यार्थियों ने रामायण, महाभारत, पंचतत्त्व और भारतीय संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। नृत्य, संगीत और नाट्य मंचन के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने का संदेश दिया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना की। समारोह में अभिभावकों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

देव समाज प्रकोष्ठ की जिला व मंडल कार्यकारिणी घोषित, सतीश लाल शर्मा बने जिला संयोजक

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। भाजपा देव समाज प्रकोष्ठ ने लाहुल-स्पीति में जिला एवं मंडल स्तर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सतीश लाल शर्मा को जिला संयोजक बनाया गया है, जबकि सोम देव मालपा और छेरिंग अंगरूप को जिला सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। स्पीति मंडल में कलजंग सोनम संयोजक तथा चेयरिंग अंगचुक और तेंजिन डोलताल सह-संयोजक होंगे। उदयपुर मंडल में छतर सिंह संयोजक, बचन सिंह और प्रकाश सह-संयोजक बनाए गए हैं। केलांग मंडल में दिनेश संयोजक तथा मनोज और नरेंद्र पॉल सह-संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है।

तंबाकू के दुष्प्रभावों के खिलाफ किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। स्वास्थ्य विभाग सोलन की ओर से नगर निगम कार्यालय में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता ने की। उन्होंने तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए लोगों से परिवार और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई।

माउंट मौर्य स्कूल में धूमधाम से मनाई दीपावली

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। माउंट मौर्य इंटरनेशनल स्कूल में दीपावली उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में चिनार हाउस ने प्रथम, स्प्रूस हाउस ने द्वितीय तथा सिल्वर और टीक हाउस ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य योगेश ठाकुर ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली प्रेम, सद्भावना और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।



पीसीएस नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों से पंजाब की सियासत गरमाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा के घोषित परिणाम पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिना पैसे और बिना सिफारिश के चयन करने के सरकार के दावों की वास्तविकता सामने आनी चाहिए। जाखड़ ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर परीक्षा परिणाम में कुछ परीक्षा केंद्रों और विशेष कमरों से असामान्य संख्या में अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाए हैं।



पीसीएस के परिणाम में गड़बड़ी के आरोप, सुनील जाखड़ ने मांगी सीबीआई जांच।

सुनील जाखड़ ने दावा किया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम में कुछ परीक्षा केंद्रों और कमरों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। उनके अनुसार, कुछ परीक्षा कक्षों में बैठे 10 से 11 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसके अलावा रोल नंबरों के क्रम में तीन से चार लगातार नंबर वाले अभ्यर्थियों के कुल 86 चयन होने का दावा भी किया गया है। जाखड़ ने सवाल उठाया कि क्या रोल नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हुई थी या कुछ अभ्यर्थियों को योजनाबद्ध तरीके से लगातार रोल नंबर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में किसी एक केंद्र या कुछ चुनिंदा कमरों से लगभग एक चौथाई अभ्यर्थियों का सफल होना संदेह पैदा करता है। हालांकि, इन आरोपों और आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

पीपीएससी ने चार नवंबर को पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 331 पद भरे जाने हैं। आयोग ने मुख्य परीक्षा के आधार पर 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया है। मुख्य परीक्षा का आयोजन एक से 10 अप्रैल 2026 तक किया गया था। वहीं, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 11 से 17 नवंबर तक पटियाला स्थित आयोग कार्यालय में की जानी है। जाखड़ ने मांग की है कि चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जांच होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका दूर की जा सके।

भाजपा अध्यक्ष ने पीसीएस परीक्षा के कथित विवाद को नीट पेपर लीक मामले से जोड़ते हुए कहा कि पंजाब के युवाओं को दोनों मामलों के बीच अंतर समझना चाहिए। उन्होंने इससे पहले नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में सामने आए विवादों का भी उल्लेख किया।

रवनीत बिट्टू ने भी सरकार को घेरा

पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर परीक्षा केंद्रों और कमरों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के आंकड़े साझा किए। बिट्टू के अनुसार, सेंटर-7 के कमरा नंबर आठ में परीक्षा देने वाले 24 अभ्यर्थियों में से 11 को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जो लगभग 45.8 प्रतिशत है। इसी तरह सेंटर-11 और सेंटर-4 के कुछ कमरों से 10-10 अभ्यर्थियों के चयन का दावा किया गया है। उन्होंने सेंटर-8 में कुल चयन दर 24.21 प्रतिशत और सेंटर-1 के कमरा नंबर एक से सात तक चयन दर केवल 2.89 प्रतिशत होने का उल्लेख किया। बिट्टू ने कहा कि अलग-अलग परीक्षा केंद्रों और कमरों के परिणामों में इतना अंतर होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि साक्षात्कार प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जाए और किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा सीबीआई से जांच करवाई जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह विवाद केवल एक भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के उन हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, जो वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी सेवा में जाने का सपना देखते हैं। जाखड़ ने परीक्षा केंद्रों, रोल नंबर आवंटन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अंतिम चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।

झोटा हत्याकांड में सीबीआई ने फिर संभाली जांच की कमान

पहली फायरिंग के सुराग तलाशने में जुटी फोरेंसिक टीम, पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, मानसा

पंजाब के मानसा में एंटी-डग टास्क फोर्स के नेता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बार फिर जांच तेज कर दी है। बुधवार को करीब 15 दिन बाद सीबीआई की टीम दोबारा मानसा पहुंची। इस दौरान टीम ने स्थानीय प्रशासन की मदद से मामले के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक अश्विनी कुमार की दुकान का मलबा अपनी निगरानी में हटवाया। जांच एजेंसी का उद्देश्य मलबे में मौजूद संभावित साक्ष्यों और महत्वपूर्ण सुरागों को जुटाना है। चंडीगढ़ से पहुंची फोरेंसिक टीम के अधिकारियों ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। जांच के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।



डीएसपी गुरप्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और विभिन्न थानों के प्रभारी भी मौके पर तैनात किए गए थे। जांच प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए रेलवे फाटक से बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात बंद करवा दिया गया। इसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से मेडिकल स्टोर के अंदर पड़ा मलबा हटवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरी कार्रवाई सीबीआई अधिकारियों की निगरानी में हुई। मलबे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसके लिए मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। हटाए गए मलबे को एसडीएम कार्यालय के पास सुरक्षित रखवाया गया, ताकि फोरेंसिक जांच के दौरान उसकी पड़ताल की जा सके। देर शाम तक जांच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया चलती रही।

पहली फायरिंग से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई पहले भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन मेडिकल स्टोर से की गई पहली फायरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुराग उस समय नहीं मिल पाए थे। इसी वजह से जांच एजेंसी ने दोबारा दुकान के मलबे की जांच करने का फैसला लिया। अब फोरेंसिक विशेषज्ञ मलबे और घटनास्थल से मिलने वाली अन्य वस्तुओं की जांच करेंगे। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के समय दुकान में क्या परिस्थितियां थीं और वहां से कौन-कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं। इस कार्रवाई को हत्या के मामले की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दूसरी ओर, अश्विनी कुमार की मेडिकल स्टोर की दुकान गिराए जाने के मामले में भी कानूनी कार्रवाई की गई है। थाना सिटी-2 में करीब 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्ति जेसीबी मशीन की मदद से दुकान को गिरा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने जांच में सहयोग के लिए एसडीएम बलजीत कौर की निगरानी में एक विशेष कमेटी का गठन किया है। नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी और तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

प्रशासन की ओर से गठित कमेटी में डीएसपी, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, पंजाब पावरकाम के एक्सईएन, फोरेंसिक जांच लैब रोटरी के प्रभारी, बीडीपीओ और नगर कौंसिल के जूनियर इंजीनियर को शामिल किया गया है। कमेटी की जिम्मेदारी मामले से संबंधित प्रशासनिक पहलुओं की जांच और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। सीबीआई की कार्रवाई के दौरान परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका जवान बेटा नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि वारदात वाले दिन पुलिस सतर्कता बरतती तो शायद उनका बेटा आज जीवित होता। भीम सिंह ने कहा कि वह मानसा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।

जालंधर में नकाबपोश हमलावरों ने घर और गाड़ी पर बरसाई गोलियां

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर । गुरु नानक नगर में बुधवार देर रात बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों ने एक घर और बाहर खड़ी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आरोपितों ने गाड़ी पर चार और मकान पर दो गोलियां चलाईं। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही एसीपी नॉर्थ करनैल सिंह, सीआईए स्टाफ के इंचार्ज रविंदर कुमार और थाना नंबर-1 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के अनुसार, साहिल नाम का युवक पिछले कुछ महीनों से गुरु नानक नगर में किराये के मकान में अपने माता-पिता और पत्नी के साथ रह रहा है। बुधवार रात करीब 10 बजे अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन बाद में घर और गाड़ी पर फायरिंग की जानकारी मिलने पर इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वारदात के बाद बाइक सवार दोनों नकाबपोश युवक तेजी से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने साहिल की गाड़ी और मकान को निशाना बनाया। हालांकि, फायरिंग के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि साहिल का आसपास के लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं है। एसीपी नॉर्थ करनैल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं।

मार्च 2027 तक कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया चुकाने की मांगी योजना

डीए बकाया विवाद में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

मुख्य सचिव को राहत, लेकिन लंबित देनदारियों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान से जुड़े मामले में राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही सिविल अवमानना मामले में भी सरकार और अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पंजाब सरकार को मार्च 2027 तक लंबित डीए और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान की योजना पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि वह बकाया राशि में से कितनी रकम जारी कर सकती है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वर्तमान में डीए की दर 53 प्रतिशत है। सरकार को सकारात्मक रुख अपनाते हुए भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।



सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाये के भुगतान की समयसीमा और वित्तीय व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी। पीठ ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस तरह और कितने समय में लंबित देनदारियों का भुगतान करेगी। अदालत ने मार्च 2027 तक भुगतान की योजना प्रस्तुत करने को कहा है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने बकाये के निपटारे को लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मिल सकेगी।

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने तीन अगस्त 2026 को आदेश दिया था कि पंजाब सरकार अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों का भुगतान उसी दर से करे, जिस दर से राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को डीए दिया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर भी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 30 अक्टूबर के हाई कोर्ट के आदेशों का अवलोकन करने के बाद आपराधिक अवमानना की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सिविल अवमानना मामले में भी फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा। सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की तुलना में विशेष सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में उनके कामकाज में जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की अपील दाखिल करने के संबंध में कथित तौर पर गलत तथ्य पेश किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी।

विदेशी हैंडलरों से जुड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश

अमृतसर में 34 किलो हेरोइन और हथियारों समेत 16 तस्कर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में अवैध हथियारों और नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 16 आरोपितों को गिरफ्तार कर हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, दो अत्याधुनिक उजी गन, दो हैंड ग्रेनेड, 34 किलोग्राम हेरोइन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से विदेश में बैठे हैंडलरों के इशारे पर संचालित हो रहे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने फायरिंग की तीन घटनाओं को भी सुलझाने का दावा किया है।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपित विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे। ये विदेशी हैंडलर स्थानीय स्तर पर अपने नेटवर्क के माध्यम से अवैध हथियारों की आपूर्ति करवाने में मदद कर रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बरामद हथियारों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क को विदेश से कौन संचालित कर रहा था और हथियारों तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति किन माध्यमों से की जा रही थी।



इस पूरे मामले में थाना घरिंडा, थाना ब्यास, थाना मेहता, थाना लोपोके और थाना छेहरटा में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस इन मामलों को आपस में जोड़कर तस्करी नेटवर्क की पूरी गतिविधियों की जांच कर रही है। बरामद हथियारों, विस्फोटकों और हेरोइन के स्रोत का पता लगाने के साथ आरोपितों के आपसी संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि गिरफ्तार आरोपितों ने अब तक किन लोगों तक हथियार और नशीले पदार्थ पहुंचाए हैं।

विदेश में बैठे संचालकों तक पहुंचने की कोशिश

अमृतसर ग्रामीण पुलिस अब तस्करी नेटवर्क की पिछली और आगे की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच का मुख्य उद्देश्य विदेश में बैठे हैंडलरों, स्थानीय तस्करों और हथियारों की आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों तक पहुंचना है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बरामद 34 किलोग्राम हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किन क्षेत्रों में की जानी थी। पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध हथियारों और नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे संगठित नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करना पुलिस की प्राथमिकता है।

अमृतसर स्वास्थ्य विभाग के आदेश में तारीख की बड़ी लापरवाही उजागर

ड्यूटी आदेश में तारीख की गलती, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर । स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी लापरवाही को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इस बार अमृतसर के सिविल सर्जन कार्यालय की एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी आदेश में हुई इस गलती को देखकर लोग भी हैरान हैं। मामला दीपावली और भैया दूज के अवसर पर श्री राम आश्रम (106 प्रीतम नगर, 100 फुटी रोड, सुल्तानविंड रोड) में आने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगाने से जुड़ा है। विभाग की ओर से पांच नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया था, लेकिन इस आदेश में ही तारीख संबंधी ऐसी गलती कर दी गई, जिसने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। जानकारी के अनुसार, सिविल सर्जन कार्यालय अमृतसर की ओर से 30 अक्तूबर 2026 को दफ्तरी आदेश संख्या 1508 जारी किया गया था। इसके तहत श्री राम आश्रम में पांच नवंबर से 11 नवंबर तक डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान आश्रम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और साधु-संतों को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। हैरानी की बात यह है कि आदेश जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर होने के बजाय आधिकारिक पत्र पर 30-11-2026 दर्ज कर दी गई। यानी विभाग ने नवंबर महीने की शुरुआत से पहले ही पूरे महीने को पार करते हुए अंतिम तारीख लिख दी। इस एक गलती ने विभागीय आदेश की विश्वसनीयता और उसे तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या यह केवल टाइपिंग की त्रुटि है या फिर अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों की जांच में बरती गई लापरवाही का परिणाम है? विभाग की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या सुधारात्मक कार्रवाई सामने आने की जानकारी नहीं है। हालांकि, इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज तैयार करने और उन्हें जारी करने से पहले उचित जांच की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। लोगों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस चूक का संज्ञान लेकर जिम्मेदारी तय करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों में इस तरह की हास्यास्पद गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

त्योहारों से पहले जालंधर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था



भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख बाजारों का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बाजारों में भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह के निर्देशों पर अधिकारियों ने विभिन्न मार्केट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और दुकानदारों के साथ बैठकें कीं। इनमें त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़, ट्रैफिक जाम की समस्या और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और बाजारों में अनावश्यक भीड़ तथा यातायात बाधित होने की स्थिति पैदा न होने दें।

पंजाबी गायक कमल ग्रेवाल पर गैंगस्टर की नजर, पांच करोड़ की रंगदारी से दहशत

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना । प्रसिद्ध पंजाबी गायक कमलजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ कमल ग्रेवाल से कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर गायक के लाइव कार्यक्रम बंद करवाने और जान से मारने की धमकी दी गई है। परिवार की सुरक्षा को लेकर गायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके आधार पर थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने कथित आरोपी गिल्ली राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) के तहत मामला दर्ज किया है।

कमल ग्रेवाल ने शिकायत में बताया कि सराभा नगर में उनकी म्यूजिक कंपनी है, जहां कर्मचारी उनके लाइव कार्यक्रमों की बुकिंग संभालते हैं। 20 अक्टूबर को पटियाला में दशहरा कार्यक्रम के दौरान उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से कई मिस्ड कॉल और वॉयस मैसेज आए। व्यस्तता के कारण वह कॉल नहीं उठा सके। अगले दिन संदेश सुनने पर कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य गिल्ली राणा बताते हुए पांच करोड़ रुपये मांगे।



इसके बाद एक नवंबर को उनके कार्यालय में दोबारा फोन कर रंगदारी के लिए दबाव बनाया गया। वॉयस मैसेज में आरोपी ने गायक को धमकाते हुए कहा कि यदि उसने कार्यक्रम बंद नहीं किए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर जगराज कौर के अनुसार पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट विदेशी नंबर, वीपीएन और आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में इंटरनेट कॉलिंग या वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल होने की आशंका है।

स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दो वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार ने डॉ. अनिल कुमार गोयल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक का अस्थायी कार्यभार दिया है। वहीं, डॉ. सिमी मल्होत्रा को निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (एसबी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, डॉ. अनिल कुमार गोयल वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अगले आदेश तक निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का अस्थायी कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत डॉ. सिमी मल्होत्रा को निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (एसबी) का अस्थायी प्रभार सौंपा गया है। दोनों अधिकारियों को विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए यह दायित्व दिया गया है।

एनओसी प्रतिबंध के बावजूद मलौद तहसील में रजिस्ट्रियों पर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना । पंजाब सरकार की ओर से राज्य की सभी तहसीलों में बिना एनओसी के जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रियां करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद लुधियाना जिले की मलौद तहसील में कथित तौर पर सरकारी आदेशों की अनदेखी कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले के उजागर होने के बाद तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायतकर्ता वरिंदर सिंह के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को मलौद तहसील में वसीका नंबर 769 और 770 की रजिस्ट्रियां बिना एनओसी के की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों रजिस्ट्रियां लुधियाना जिले के गिलां गांव की जमीन से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मलौद तहसील में तैनात सब-रजिस्ट्रार को कानूनी नोटिस भी भेजा है। उनका कहना है कि जब सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं तो ऐसे में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि मलौद तहसील में इससे पहले भी रजिस्ट्रियों से जुड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आ चुका है। उस समय लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां तैनात सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसके बावजूद अब दोबारा इस तरह के आरोप सामने आने से तहसील में रजिस्ट्री प्रक्रिया की निगरानी और सरकारी आदेशों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।



सरकारी आदेशों की अनदेखी का आरोप, शिकायतकर्ता ने सब-रजिस्ट्रार को भेजा नोटिस

घरवापसी

पुनर्जीवित अकाली दल के कई नेता और एसजीपीसी सदस्य भी सुखबीर बादल के संपर्क में आए

चंदूमाजरा की अकाली दल में वापसी के आसार तेज

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

पंजाब की राजनीति में आने वाले दिनों में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। पुनर्जीवित अकाली दल को छोड़ने के बाद वरिष्ठ अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा के शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में संभावना जताई जा रही है कि वह दीपावली से पहले या त्योहार के एक-दो दिन बाद सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल में वापसी कर सकते हैं। हालांकि, उनके दोबारा पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि ऐसा होता है तो इसे पंजाब की सियासत में शिरोमणि अकाली दल के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाएगा।

प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा के इस्तीफे से पुनर्जीवित अकाली दल को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पटियाला और श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। वह इन दोनों संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ऐसे में उनके पार्टी छोड़ने से पुनर्जीवित अकाली दल की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल में वापस लाने के लिए पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल का एक करीबी नेता लगातार उनके संपर्क में था।



पंजाब की सियासत में नए समीकरण बनने के आसार

पुराने नेताओं की घर वापसी से मजबूत होगी पार्टी

शिरोमणि अकाली दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में गए कई नेताओं के दोबारा पार्टी के संपर्क में आने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ नेता अपने मौजूदा राजनीतिक दलों में अपेक्षित सम्मान और महत्व नहीं मिलने के कारण नए विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में अकाली दल के लिए पुराने नेताओं की घर वापसी संगठन को मजबूत करने का अवसर बन सकती है। पार्टी नेतृत्व भी अपने पुराने राजनीतिक आधार और पंथक नेताओं को फिर से साथ लाने की कोशिश में जुटा बताया जा रहा है। पंजाब की राजनीति में इन संभावित बदलावों का कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

भाजपा-अकाली दल गठबंधन की अटकलें तेज

दूसरी ओर, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोबारा गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों दलों के बीच इस संबंध में बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। हालांकि, गठबंधन को लेकर अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि दोनों दल फिर से एक साथ आते हैं तो पंजाब की आगामी चुनावी राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।

नड्डा ने परखी एम्स अवंतीपोरा की निर्माण प्रगति

कश्मीर में उन्नत चिकित्सा, विशेषज्ञ उपचार और शोध सुविधाओं का होगा विस्तार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एम्स अवंतीपोरा की निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू के साथ दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों, बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया।



समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और अब तक हुई प्रगति का आकलन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में उन क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि संस्थान को जल्द से जल्द पूरी तरह तैयार कर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचालित किया जा सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि एम्स अवंतीपोरा का संचालन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे लोगों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

◆एम्स परियोजना की समीक्षा में निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने पर विशेष जोर

एम्स अवंतीपोरा को कश्मीर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ उपचार, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पूरी तरह संचालित होने से दक्षिण कश्मीर सहित घाटी के अन्य जिलों और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। संस्थान में विभिन्न गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

फिलहाल गंभीर बीमारियों और जटिल उपचार के लिए जम्मू-कश्मीर के कई मरीजों को दिल्ली, चंडीगढ़ और देश के अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों का रुख करना पड़ता है। एम्स के शुरू होने से ऐसे मरीजों को अपने क्षेत्र में ही उन्नत उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय तथा यात्रा पर होने वाला खर्च भी बच सकेगा।

चिकित्सा शिक्षा और शोध को भी मिलेगा बढ़ावा

एम्स अवंतीपोरा केवल उपचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहां मेडिकल विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार की संयुक्त पहल को प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना की नियमित समीक्षा और निर्माण कार्यों में तेजी से संस्थान को जल्द शुरू करने की उम्मीद है। इससे कश्मीर में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत होगा।

रामबन में कमर्शियल वाहनों की वन-वे व्यवस्था लागू

शान पैलेस से प्रवेश, कैफेटेरिया चौक से वाहनों की निकासी होगी सुनिश्चित

भारतेंदु संवाददाता, उधमपुर

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रामबन शहर में लगातार लगने वाले जाम और यातायात की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर में कमर्शियल यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के लिए वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था शुरू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद अलीयास खान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले दो महीने तक अथवा आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी।

◆बाजारों में जाम घटाने के लिए प्रशासन ने यातायात संचालन का बदला स्वरूप



(एआई निर्मित तस्वीर)

प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शहर के व्यस्त बाजारों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। आदेश के अनुसार, शहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी कमर्शियल यात्री वाहनों को निर्धारित एकतरफा मार्ग का पालन करना होगा। इनमें सूमो, बसें, मिनी बसें और इको वाहन शामिल हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के लोड कैरियर वाहनों पर भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित रूट के अनुसार, सभी कमर्शियल वाहनों को शान पैलेस नाके से रामबन शहर में प्रवेश करना होगा। यहां से वाहन बोवली बाजार, टी-चौक और बस स्टैंड होते हुए कैफेटेरिया चौक तक पहुंचेंगे। इसके बाद वाहनों को निर्धारित निकासी मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कैफेटेरिया चौक की तरफ से बस स्टैंड में कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस मार्ग का इस्तेमाल केवल शहर से बाहर निकलने के लिए किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को एक दिशा में संचालित करना है, ताकि संकरी सड़कों और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में आमने-सामने वाहनों के आने से पैदा होने वाली जाम की स्थिति को रोका जा सके। विशेष रूप से बस स्टैंड, टी-चौक और बोवली बाजार के आसपास यातायात को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया है। प्रशासन ने मालवाहक वाहनों के संचालन को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचित मार्गों पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सामान की लोडिंग और अनलोडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

पुलिस और परिवहन विभाग को सख्ती से पालन कराने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने नई यातायात व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामबन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक (राष्ट्रीय राजमार्ग) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था की निगरानी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। आदेश की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की संबंधित धारा के तहत जारी किया गया है। प्रशासन उम्मीद है कि वन-वे व्यवस्था से रामबन शहर में यातायात संचालन अधिक सुचारू होगा। दो महीने तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकेगा और जरूरत के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा।

कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी पर आधुनिक हीटरों का बढ़ता असर, कारीगर चिंतित

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

कश्मीर में सर्दी की दस्तक के साथ ही पारंपरिक कांगड़ी बनाने का काम तेज हो गया है, लेकिन आधुनिक हीटरों और बिजली से चलने वाले गर्म उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस पारंपरिक शिल्प के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। कभी कश्मीरी परिवारों की अनिवार्य जरूरत रही कांगड़ी अब धीरे-धीरे अपनी पुरानी पहचान और बाजार खो रही है। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले का चरार-ए-शरीफ अपनी खास कांगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के कारीगर इस पारंपरिक कला को बचाने के साथ इससे जुड़ी अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।



कांगड़ी मिट्टी के छोटे बर्तन और विलो (लचीली लकड़ी) की पतली पट्टियों से तैयार की जाती है। कश्मीरी लोग सर्दियों में इसे फिरन के नीचे रखकर ठंड से बचते हैं। यह केवल गर्माहट देने का साधन नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा रही है। हालांकि, बदलते समय और आधुनिक तकनीक के कारण इसका इस्तेमाल लगातार कम हो रहा है।

◆चरार-ए-शरीफ के शिल्पकार आर्थिक मदद और प्रशिक्षण से विरासत बचाने में जुटे

विलो-विकर शिल्प में वर्ष 2022 का केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार प्राप्त करने वाले कारीगर बशीर अहमद डार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कांगड़ी की मांग में काफी गिरावट आई है। पहले लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लोग बिजली से चलने वाले हीटरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। करीब 40 से 50 वर्षों से इस काम से जुड़े डार की कार्यशाला में आठ लोग काम करते हैं। यहां हर साल लगभग पांच से छह हजार कांगड़ियां तैयार की जाती हैं। इनकी बिक्री का मुख्य सीजन नवंबर से फरवरी तक रहता है।

चरार-ए-शरीफ की कांगड़ियों की अपनी अलग पहचान है। यहां सामान्य इस्तेमाल के अलावा दुल्हन के लिए विशेष रूप से तैयार की जाने वाली 'महरीन कांगड़ी' भी बनाई जाती है। इसके अलावा सजावटी और छोटे आकार की कांगड़ियां भी तैयार की जाती हैं। कारीगर पारंपरिक शिल्प को आधुनिक पसंद के अनुरूप ढालने के लिए नए डिजाइन और आकार के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ताकि बाजार में इसकी मांग बनाए रखी जा सके।

दीपावली पर जम्मू में पटाखों की बिक्री के लिए दस स्थान निर्धारित

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । दीपावली के त्योहार को देखते हुए जम्मू जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए शहर में 10 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री करने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बिक्री के लिए नियम भी तय कर दिए हैं। इसके तहत नाबालिगों को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी और सभी विक्रेताओं को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अनुसार ही बिक्री करनी होगी। डिप्टी कमिश्नर जम्मू मिंगा शेरपा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पटाखों की बिक्री में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों का सामान जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के थोक और खुदरा विक्रेताओं को प्रत्येक उत्पाद पर अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करना अनिवार्य होगा। बिना एमआरपी वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर विक्रेताओं ने अस्थायी शेड बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रेम नगर स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जेडीए पार्किंग में शुक्रवार से थोक और शनिवार से खुदरा बिक्री शुरू होने की संभावना है।

◆नाबालिगों के पटाखे बेचने पर रोक, एमआरपी अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

महबूबा मुफ्ती का पीडीपी में दबदबा कायम लगातार पांचवीं बार चुनी गईं अध्यक्ष

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लगातार पांचवीं बार पार्टी का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। उनके पुनर्निर्वाचन के साथ ही पार्टी में उनका नेतृत्व एक बार फिर कायम हो गया है। इसे संगठन के भीतर उनके नेतृत्व और राजनीतिक अनुभव पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। पांचवीं बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब उनके सामने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर पीडीपी की भूमिका को प्रभावी बनाने की चुनौती होगी।



जम्मू-कश्मीर के सियासी हालात में संगठन मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर पकड़ बढ़ाने की चुनौती

महबूबा मुफ्ती का दोबारा अध्यक्ष चुना जाना ऐसे समय में हुआ है, जब जम्मू-कश्मीर की राजनीति कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा में है। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक अधिकारों, स्थानीय पहचान और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं।

महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अपनी राय रखती रही हैं। पीडीपी भी राज्य के अधिकारों और विशेष पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपनी राजनीतिक आवाज उठाती रही है। पार्टी का मानना है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और समस्याओं को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिलनी चाहिए। हाल ही में दो नवंबर को श्रीनगर में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के दौरान महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) पर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हितों और स्वायत्तता के मुद्दे पर समझौता करने का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच सार्थक संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। उनके इस बयान को प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया।

मुख्यमंत्री उमर ने शिक्षा में नैतिकता और स्वतंत्र चिंतन पर दिया जोर

विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर विवेकशील नागरिक बनने की दी सीख

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना या मेधावी विद्यार्थियों की सूची में स्थान बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार करना है, जो ज्ञान, विवेक, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा की वास्तविक सार्थकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को यह बात कहते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उनमें स्वतंत्र चिंतन, तार्किक क्षमता और सही-गलत का अंतर समझने की योग्यता विकसित करना जरूरी है। साथ ही उन्हें समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए।



उमर अब्दुल्ला की सलाह, होमवर्क और असाइनमेंट एआई से न कराएं।

जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वार्षिक 'ऑनर एंड एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से निर्भीक होकर सवाल पूछने और अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना भी है। इसके लिए उनमें जिज्ञासा, आत्मविश्वास और तार्किक सोच विकसित होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को समझने और उनके बारे में सवाल करने की आदत डालनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आज के विद्यार्थी ऐसी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनसे पिछली पीढ़ियां काफी हद तक अनजान थीं। ऐसे में तकनीक के सकारात्मक इस्तेमाल की समझ विकसित करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करने की सलाह दी। कहा कि तकनीक को ज्ञान हासिल करने, नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए, न कि अपनी मेहनत और रचनात्मकता का विकल्प।

समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर (केएनओ) के अनुसार, समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 99 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित अन्य मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इसके अलावा 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी उनके समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार, शिक्षकों और संस्थानों के प्रयासों का भी परिणाम है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।

जम्मू-कश्मीर में सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन व्यवस्था होगी आधुनिक

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री जावेद अहमद राणा ने दूरदराज क्षेत्रों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और ऑनलाइन सेवाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मंगलवार को जम्मू में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग को नागरिक केंद्रित और तकनीक आधारित संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होने से स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने लाइसेंस जारी करने और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अनावश्यक देरी खत्म करने को कहा।

जम्मू-कश्मीर में स्व-घोषणा से उद्योग स्थापना आसान, निवेशकों को मिलेगी राहत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब पात्र उद्यमियों को कारोबार शुरू करने से पहले विभिन्न विभागों से मंजूरियां लेने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। वे स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर सैद्धांतिक मंजूरी का प्रमाणपत्र प्राप्त कर उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा निवेश से जुड़े अनुमोदनों के लिए कार्यकारी समिति को एकल नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पात्र उद्यमियों को तीन साल तक नियमित सरकारी निरीक्षण से भी राहत मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने चार नवंबर को महाप्रशासनिक विभाग के माध्यम से अधिसूचनाएं जारी कर जम्मू-कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। इसका उद्देश्य निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत देना, मंजूरियों में देरी कम करना और प्रदेश में निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

एकल एजेंसी करेगी मंजूरियों का समन्वय : नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति निवेशकों के लिए एकल संपर्क एजेंसी के रूप में काम करेगी। उद्योग स्थापना, भवन निर्माण, बिजली-पानी कनेक्शन, अग्निशमन सुरक्षा, पर्यावरण, फैक्टरी लाइसेंस और कारोबार संचालन से संबंधित अनुमोदनों के लिए विभिन्न विभागों के बीच यही समिति समन्वय करेगी। जिला अधिकारप्राप्त समितियां भी इसमें सहयोग करेंगी। इससे उद्यमियों को अलग-अलग विभागों की प्रक्रियाओं से गुजरने की परेशानी कम होगी।

तीन से 30 कार्यदिवस में मिलेगी मंजूरी : पात्र उद्यमी जिला अधिकारप्राप्त समिति के समक्ष कारोबार स्थापित करने की मंशा संबंधी स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सैद्धांतिक मंजूरी का प्रमाणपत्र (सीआईपीए) प्राप्त कर सकेंगे। स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाली इकाइयों को तीन कार्यदिवस में, जबकि औद्योगिक पार्कों से बाहर स्थापित होने वाले नए उद्यमों को 30 कार्यदिवस में प्रमाणपत्र जारी करना होगा। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर मंजूरी स्वत: स्वीकृत मानी जाएगी। यह प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा।

निरीक्षण और दोहरे लाइसेंस से राहत : नई व्यवस्था में प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले पात्र उद्यमों को तीन साल तक नियमित सरकारी निरीक्षण से संरक्षण मिलेगा। हालांकि गंभीर शिकायतों और कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारियों की अनुमति से निरीक्षण किया जा सकेगा। इसके अलावा स्व-प्रमाणन और तीसरे पक्ष से प्रमाणन की व्यवस्था भी की गई है।

पांच दिन बाद एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंची रूबीना की सुरक्षित वतन वापसी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ के किरनी गांव की रहने वाली 44 वर्षीय रूबीना कौसर पांच दिन बाद बुधवार को सुरक्षित भारत लौट आईं। वह अनजाने में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर पाकिस्तान पहुंच गई थीं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने चकां दा बाग क्रॉसिंग पॉइंट के माध्यम से उन्हें उनकी भेड़-बकरियों सहित भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। रूबीना की सुरक्षित वापसी से उनके परिवार और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है।



जानकारी के अनुसार, रूबीना कौसर पत्नी मुहम्मद शफीक निवासी किरनी गांव पांच दिन पहले रोजाना की तरह अपनी भेड़-बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थीं। इसी दौरान वह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनजाने में नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गईं। जब काफी समय तक वह घर नहीं लौटीं तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। बाद में उनके पाकिस्तान की सीमा में पहुंचने की जानकारी सामने आई। इसके बाद परिवार को उनकी सुरक्षा और सकुशल वापसी की चिंता सताने लगी।

मामले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय अधिकारियों ने रूबीना कौसर की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। सीमावर्ती क्षेत्रों में अनजाने में सीमा पार करने की घटनाओं में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपर्क किया जाता है। इसी समन्वय के माध्यम से उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ।

पांच दिनों तक पाकिस्तान में रहने के बाद बुधवार को पाकिस्तानी अधिकारियों ने चकां दा बाग क्रॉसिंग पॉइंट पर रूबीना को भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया। इस दौरान उनकी भेड़-बकरियों को भी वापस सौंपा गया। इसके बाद उनकी भारत वापसी सुनिश्चित हुई। उनके साथ पशुधन की वापसी भी परिवार के लिए बड़ी राहत रही, क्योंकि वह रोजी-रोटी के सिलसिले में ही पशुओं को चराने के लिए निकली थीं।

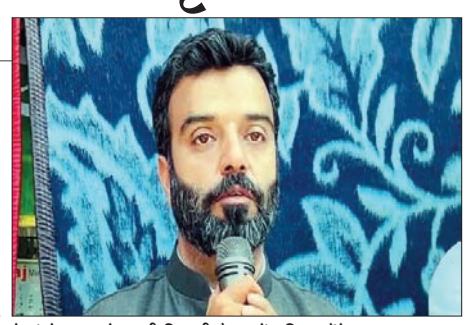
रूबीना के परिजन पिछले पांच दिनों से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान परिवार के सदस्य उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। बुधवार को उनकी सकुशल वापसी की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल बन गया।

बगावत पार्टी नेतृत्व पर भाजपा के सामने झुकने का आरोप, अधिकारों की लड़ाई तेज करने का एलान

रुहुल्लाह ने नेकां नेतृत्व और भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) से इस्तीफे का एलान करने के बाद सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भाजपा और अपनी पूर्व पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नेकां पर भाजपा के सामने समर्पण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के प्रति भाजपा की नीतियों और उसके राजनीतिक रवैये का लगातार विरोध करते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को सामान्य बताने और भाजपा की नीतियों को स्वीकार करने की कोशिशों का वह विरोध करेंगे।



नेकां से अलग होकर भी सियासी मैदान में सक्रिय रहेंगे रुहुल्लाह

रुहुल्लाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका टकराव पार्टी के भाजपा के सामने कथित रूप से झुकने को लेकर था। वह इस राजनीतिक स्थिति को सामान्य घटनाक्रम मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार, भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और इस मुद्दे पर वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कितने भी नेता मौजूदा व्यवस्था का बचाव क्यों न करें, जम्मू-कश्मीर के हितों और अधिकारों से जुड़े सवालों पर उनका विरोध जारी रहेगा।

भाजपा नेता राम माधव के बयान पर भी रुहुल्लाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राम माधव ने कहा था कि तीन नवंबर को बडगाम में आयोजित रुहुल्लाह की रैली को भाजपा समर्थकों का आशीर्वाद प्राप्त था। इस पर सांसद ने कहा कि वह राम माधव को व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं हैं और न ही उनका उनसे कोई संबंध है।

उन्होंने इस बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। रुहुल्लाह ने कहा कि राम माधव के दावे के संबंध में पार्टी के नेताओं से सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि संभव है कि उनके बीच कोई बातचीत हुई हो। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों को भाजपा के समर्थन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

रुहुल्लाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रति भाजपा की नीतियों, उसके आक्रामक राजनीतिक रवैये और प्रदेश के साथ किए जा रहे व्यवहार को वह चुनौती देते रहेंगे। उन्होंने साफ किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या नेताओं के बयानों से उनका रुख नहीं बदलेगा। उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर की मौजूदा व्यवस्था को सामान्य बताने के प्रयासों का विरोध करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

गौरतलब है कि तीन नवंबर को बडगाम में आयोजित एक सार्वजनिक रैली के दौरान रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और श्रीनगर लोकसभा सीट से इस्तीफे का एलान किया था। वह करीब 24 वर्षों तक नेकां से जुड़े रहे।

अधिकारों और सम्मान के लिए व्यापक आंदोलन के संकेत

भाजपा नेता राम माधव ने तीन नवंबर को जम्मू दौरे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट रूप से विभाजित पार्टी बताया था। हालांकि, उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों में भाजपा की किसी भूमिका से इनकार किया था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। रुहुल्लाह ने अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर संकेत दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान की बहाली के लिए व्यापक आंदोलन खड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पार्टी से अलग होने के बाद उनके इस रुख से स्पष्ट है कि वह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में उनके अगले राजनीतिक कदमों पर सभी की नजरें रहेंगी।रुहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया था। उनका विशेष रूप से कहना था कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पार्टी अपने वादों के अनुरूप आगे नहीं बढ़ी। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी जताई थी।

सत्ता से जवाब

मांगती युवा पीढ़ी, लोकतंत्र और अधिकारों की नई जंग



दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकारों के खिलाफ जनता, छात्रों और युवाओं का असंतोष लगातार सामने आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और मीडिया पर सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर विभिन्न देशों में आंदोलन तेज हुए हैं। इन आंदोलनों में जेन जी यानी नई पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी ने विश्व राजनीति में नए बदलाव की संभावनाएं पैदा की हैं। हंगरी, सर्बिया, ब्राजील और इजरायल जैसे देशों के राजनीतिक घटनाक्रमों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। फ्रांस और इटली में भी छात्र विश्वविद्यालयों की बढ़ती फीस, बेरोजगारी और शिक्षा के गिरते स्तर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

सर्बिया में छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर व्यापक आंदोलन किया। युवाओं ने आम जनता को अपने साथ जोड़कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं, ब्राजील की राजनीति में भी दक्षिणपंथी विचारधारा और अमेरिकी हस्तक्षेप के बीच सत्ता संघर्ष चर्चा में रहा। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि युवा अब केवल राजनीतिक भाषणों से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई और लोकतांत्रिक अधिकारों पर जवाब चाहते हैं।

इजरायल और अमेरिका में भी राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ संघर्ष, बढ़ती महंगाई और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों ने अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। दुनिया भर में जेन जी आंदोलनों की चर्चा के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देने में सफल होगी?

दरअसल, नई पीढ़ी अब केवल राष्ट्रवाद और धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति को स्वीकार करने के बजाय रोजगार, शिक्षा, आर्थिक अवसरों और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रही है। राजनीतिक विश्लेषण में इसे प्लास्टिक नेशनलिज्म और सत्ता केंद्रित राजनीति के खिलाफ उभरती चेतना के रूप में भी देखा जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और उद्योगपतियों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली समूह चुनावी चंदे और राजनीतिक संबंधों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।



अशोक चौबे

भारत में भी बेरोजगारी, महंगाई और चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बजाय सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं, सरकार और सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।

इसी मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एआई निर्मित चित्र।

पहली नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाने और वोट चोरी के आरोपों को लेकर महारैली आयोजित की। इस रैली में विभिन्न विपक्षी दलों की भागीदारी ने राजनीतिक एकजुटता का संदेश दिया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयोजन बताया। रैली को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। दूसरी ओर, भाजपा ने विपक्ष के आरोपों और आंदोलन की राजनीति पर सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी रही। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल करना तथा जनता तक निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना है।

नई पीढ़ी के आंदोलनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक जागरूकता और जनभागीदारी का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। युवा विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, सरकारों से जवाब मांगते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। हालांकि, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए शांतिपूर्ण तरीके, तथ्यपरक संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन जरूरी है। दुनिया भर में उभर रही यह राजनीतिक चेतना बताती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें जनता के अधिकार, संस्थाओं की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

उत्तराखंड भाजपा में नेतृत्व का सवाल : 32 सीटों का आकलन या 48 सीटों का भरोसा?



उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भाजपा की रणनीति, नेतृत्व और संभावित सीटों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? क्या पार्टी किसी दूसरे चेहरे को भी आगे ला सकती है? या फिर केंद्रीय नेतृत्व बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनावी मैदान में उतरेगा? इन सवालों को लेकर प्रदेश की राजनीति में अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

भाजपा के लिए उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। ऐसे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव से पहले नेतृत्व और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं और फैसलों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं, पार्टी संगठन भी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को गति देने में जुटा है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा चुनाव से पहले धामी के चेहरे को लेकर क्या रणनीति अपनाती है।

राजनीतिक चर्चाओं में भाजपा की संभावित सीटों को लेकर दो अलग-अलग आकलन सामने आ रहे हैं। पहला आकलन पार्टी की स्थिति को लेकर कुछ आशंकाएं जताता है, जबकि दूसरा आकलन भाजपा के लिए बेहतर चुनावी संभावनाओं की ओर संकेत करता है।

कुछ राजनीतिक चर्चाओं और स्थानीय आकलनों में भाजपा की सीटें 32 के आसपास या उससे नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह की चर्चाओं के पीछे संगठनात्मक चुनौतियों, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और कुछ क्षेत्रों में संभावित नाराजगी को आधार माना जा रहा है। हालांकि, यह केवल राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित आकलन है। इसे किसी आधिकारिक सर्वे या चुनावी परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके बावजूद इस तरह के आकलन भाजपा के लिए चुनावी तैयारियों और संगठन की मजबूती पर ध्यान देने का संकेत जरूर देते हैं।



विकास बलूनी

दूसरी ओर, भाजपा के संभावित आंतरिक आकलन को लेकर 45 से 48 सीटों तक की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। यदि इस तरह का आकलन सही साबित होता है तो यह पार्टी के लिए उत्साहजनक स्थिति हो सकती है। हालांकि, इस आकलन की भी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा भी है कि सरकार की योजनाओं, संगठन की सक्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव का चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति का पता चुनाव के नजदीक आने और जनता के रुझान से ही चलेगा।

सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है। सवाल संगठन के भीतर तालमेल, संभावित भीतरघात, पुराने और नए नेतृत्व के समीकरण तथा जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों का भी है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर चुनावी तैयारी को मजबूत करने की होगी। प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्रों में पुराने नेताओं और नए राजनीतिक चेहरों के बीच समीकरण भी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में टिकट वितरण और नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

अब सबकी निगाहें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बैठक पर टिकी हैं। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या इस बैठक में नेतृत्व को लेकर कोई स्पष्ट संदेश मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर मुहर लगेगी या भाजपा कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व चुनाव से पहले संगठन को लेकर कोई बड़ा बदलाव करने का संकेत देगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बदलते पारिवारिक परिवेश में पिता और बच्चों के रिश्तों की नई तस्वीर



एआई निर्मित चित्र।

वर्तमान में पिताओं में जो परिवर्तन परिलक्षित हुआ है, वह एक साहसिक और खुशगवार पहलू है। पहले के पिता जो विशेष रूप से अपने कार्य में लीन और पूरे परिवार के सदस्यों पर रौब जमाने वाले होते थे, उनसे बच्चे बातें करने से डरते थे। यदि यह भी मैं कहूं कि वे बात भी नहीं करते थे, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

पिता से बात मां के माध्यम से होती थी। वर्तमान में पापा के नाम का खौफ नहीं रह गया है। अब पापा सकारात्मक सोच के साथ बच्चों के एकदम करीब आ गए हैं। उनके मित्र के रूप में। यही है खुशगवार परिवर्तन जो इस आधुनिक युग में देखने में आया है। जिस पर हम गर्व कर सकते हैं।

वातावरण का असर : पूर्व की पीढ़ी के पिता की आलोचना करना आसान है, परंतु उस जमाने का वातावरण आज जितना खुलापन लिए हुए नहीं था। सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी। परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे। ऐसे में किस पर ध्यान दें और किस पर नहीं, समझ में नहीं आता था। यह भी एक कारण हो सकता है। वर्तमान में यह स्थितियां उलट हैं। आज की युवा पीढ़ी भविष्य की संभावनाओं का पहले ही विचार कर लेती है, फिर वर्तमान में निर्णय करती हैं। न्यू जनरेशन का ध्यान इस ओर रहता है कि बच्चे हो और उनका पालन-पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो। सिर्फ दो बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित वे करते हैं, वरन कई परिवार तो इससे भी आगे की सोचने लगे हैं। हांलाकि, उनकी वो सोच किस दिशा में जाएगी यह कहना मुकिल है, लेकिन वे अब एक ही बच्चे में खुश रहने का सोचती है। इसलिए समय और वातावरण दोनों का ही असर देखने को मिलता है।

मित्र की भूमिका में : वर्तमान में पिता अपने बच्चों के लाडले पापा हैं। साथ ही वे मित्र की भी भूमिका में हैं। उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। वे अपने पापा से खुले तौर पर बातचीत करते हैं। अपनी आवयकताओं की पूर्ति के लिए वे आज मां को आगे नहीं करते, वरन स्वयं उत्सुक रहते हैं, अपने पापा से बातें करने में। पहले बच्चों के लालन-पालन का संपूर्ण जिम्मा अकेले मां के कंधों पर होता था। आज वह हॉफ हो गया है।

पिता होने का सुख : पिता होने के सुख की अनुभूति इन्हीं शब्दों से होती है कि जब पिता कह उठते हैं-'यकिन, नहीं होता कि यह हमारा बच्चा है।' इसके गूढ़ अर्थ में जाएं तो वे पिता बनकर बहुत ही आनंदित है। वे आंदोलित है नन्हे-नन्हे हाथ-पैर, गोल-मटोल चेहरा देखकर। उनके पास इस आनंद को बांटने के लिए शब्द भले ही न हो, परंतु वे उसे अपने हाथों में लेकर, छूकर अपनत्व के सागर में डुबकियां लगाने को आतुर रहते हैं।

संरक्षणात्मक कवच है : एक पिता के होने और न होने को खूब परिलक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में एक सुपर सितारा नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताते हैं-'मैं जब पंद्रह वर्ष का था, तभी मेरे पिता नहीं रहे। हालांकि यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, परंतु मैं रोया नहीं और समय से पहले बड़ा हो गया। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। मैंने वह सब किया जो वे करते थे। परंतु उनका साया होना ही चाहिए था। पिता की कमी को पूरा करना नामुमकिन है, क्योंकि पिता शब्द अपने आप में एक संरक्षणात्मक कवच है।'जब कोई पूछता है-'तुम किसके बेटे हो' या 'तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?', तो यहीं से पहचान और सम्मान की शुरुआत होती है। किसी भी दस्तावेज में पिता के नाम का उल्लेख आज भी आवश्यक है। भले ही अब मां का नाम भी जोड़ा जाने लगा है, पर पिता का महत्व अभी भी बना हुआ है। पिता केवल जन्मदाता नहीं, बल्कि कठिनाइयों से लड़ना और स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



संजय एम तराणेकर

रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता जाल अब बड़े सुधारों की जरूरत



एआई निर्मित चित्र।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। देश की बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले कई दशकों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया गया है।

शुरुआती दौर में इन उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद की, लेकिन आज इनके अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग के कारण कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018-2019 में जहां 115 करोड़ बैग की खपत हुई थी, वहीं 2024-25 के दौरान यह आंकड़ा 150 करोड़ बैग को पार कर गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, जबकि उर्वरकों की खपत 150 करोड़ बैग से भी अधिक हो चुकी है। यह असंतुलन न केवल चिंताजनक है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत भी है। रासायनिक उर्वरकों का असर अब हमारे थाल तक पहुंच चुका है। गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल और यहां तक कि दूध, दही और घी भी इनके रसायनों से अछूते नहीं रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में कैंसर, हृदय घात, एलर्जी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। खेतों की स्थिति भी कम सोचनीय नहीं है।

नयमानुसार, उर्वरकों का उपयोग केवल पौधों की जड़ों के पास होना चाहिए, लेकिन पूरे खेत में इनके छिड़काव से खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है। इस खरपतवार को खत्म करने के लिए फिर भारी मात्रा में खरपतवार-नाशक दवाओं का उपयोग होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं। मिट्टी की खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए किसान और अधिक खाद डालता है, और यह दुष्चक्र हर साल मिट्टी को और अधिक बंजर बनाता जा रहा है। उर्वरक क्षेत्र में बढ़ता निवेश देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। वर्तमान में देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपए (सब्सिडी सहित) के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। विडंबना यह है कि हमारा उर्वरक उद्योग 80 प्रतिशत तक विदेशी कच्चे माल या आयातित उर्वरकों पर निर्भर है। कुल 3 लाख करोड़ रुपए में से 2.5 लाख करोड़ रुपए केवल आयात में खर्च हो जाते हैं। सरकार किसानों के कल्याण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई है। इसी सब्सिडी के कारण 40 रुपए प्रति किलो वाली यूरिया खाद किसानों को 6 रुपए प्रति किलो से भी कम दाम पर उपलब्ध है। स्थिति यह है कि यूरिया आज पशुओं के चारे से भी सस्ता हो गया है। सरकार 85 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है ताकि किसानों को यूरिया एक चाय के कप से भी कम कीमत पर मिले, लेकिन इसी कम कीमत का लाभ उठाकर बिचौलिए इसकी कालाबाजारी करते हैं और कृषि के बजाय इसका उपयोग प्लाईवुड कारखानों, कैटल फीड और मिलावटी दूध बनाने में कर रहे हैं।



राम सरन वर्मा
स्वतंत्र लेखक

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

ट्रंप की मुश्किलें बढ़ीं

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उनकी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इन चुनाव परिणामों को ट्रंप प्रशासन की नीतियों के प्रति जनता की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। मनमानी टैरिफ नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन की लागत और ईरान के साथ युद्ध ने आम अमेरिकी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होने पर अपना फैसला सुना सकती है। अब ट्रंप को शेष कार्यकाल के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर उनकी राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़ती ताकत ट्रंप के घरेलू एजेंडे को प्रभावित करेगी। कराधान, सरकारी खर्च और विधायी फैसलों को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। ट्रंप के पास टैरिफ, स्वास्थ्य सेवाओं और आव्रजन संबंधी नीतियों को लेकर कार्यकारी अधिकार तथा वीटो की शक्ति जरूर है, लेकिन संसद में विरोध के कारण उनके फैसलों को लागू करना आसान नहीं होगा। कार्यकारी शक्तियों के इस्तेमाल, नैतिक मुद्दों और विदेशी व्यावसायिक हितों की भी कड़ी जांच हो सकती है। ऐसे में ट्रंप को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय राजनीतिक विरोध का सामना करने में अधिक समय और ऊर्जा लगानी पड़ सकती है।

अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है कि घरेलू मोर्चे पर संसद का विरोध बढ़ने पर राष्ट्रपति विदेश नीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ट्रंप भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ संघर्ष और पश्चिम एशिया की अस्थिरता उनके लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। संसद में डेमोक्रेटिक प्रभाव बढ़ने से सैन्य अभियानों, उनके खर्च और रणनीतिक उद्देश्यों पर अधिक निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के बीच एकतरफा टैरिफ लगाने की नीतियों पर भी सवाल उठेंगे।

मध्यावधि चुनावों के परिणाम केवल अमेरिका की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर उसके सहयोगी और विरोधी देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी संसद में राजनीतिक शक्ति संतुलन बदलने से विदेश नीति से जुड़े फैसलों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। इससे अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी देश अपने हितों के लिए नए अवसर तलाश सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। ईरान के साथ संघर्ष, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों को लेकर संसद की निगरानी बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसका प्रभाव वैश्विक महंगाई पर भी पड़ेगा। यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अमेरिकी सहयोगियों के लिए भी बदले राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे।

भारत के लिए भी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के परिणाम काफी मायने रखते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित है। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़ती ताकत भारत-अमेरिका संबंधों में नए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कर सकती है। व्यापार वार्ताओं में जटिलता बढ़ने की संभावना है, वहीं ट्रंप घरेलू राजनीतिक दबाव कम करने के लिए आर्थिक समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं।

एकतरफा टैरिफ नीतियों पर संसदीय निगरानी बढ़ने से भारत को व्यापार वार्ताओं में अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, यह मानना उचित नहीं होगा कि डेमोक्रेटिक प्रभाव बढ़ने से अमेरिकी व्यापार नीतियां भारत के प्रति पूरी तरह लचीली हो जाएंगी। अमेरिकी बाजार तक पहुंच, घरेलू उद्योगों का संरक्षण और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दे दोनों राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आव्रजन नीति और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसरों पर भी बदले राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा रूस से कच्चे तेल की खरीद का मुद्दा भी दोनों देशों के संबंधों में चुनौती बना रह सकता है।

मध्यावधि चुनावों ने ट्रंप के शेष कार्यकाल में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ा दी है। संसद में विपक्ष की मजबूत स्थिति उनके घरेलू एजेंडे को सीमित करने के साथ विदेश नीति से जुड़े लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि, इससे अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति में तत्काल बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन ट्रंप की एकतरफा फैसले लेने की क्षमता पर अंकुश जरूर लग सकता है। ऐसे में भारत को केवल व्हाइट हाउस के साथ ही नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के दोनों दलों के साथ भी मजबूत संवाद बनाए रखना होगा। भारत के लिए यही जरूरी होगा कि अमेरिका की घरेलू राजनीतिक खींचतान का असर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर न पड़े।

- शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

जिसका नाम भी विराट और काम भी विराट

भारतीय टेलीविजन जगत में अर्चना तायडे एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपने अभिनय कौशल और विभिन्न टेलीविजन धारावाहिकों में निभाए गए किरदारों के माध्यम से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। अर्चना तायडे का जन्म 6 नवंबर 1988 को भारत में हुआ था। वह भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं और उन्हें विशेष रूप से जी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'कुबूल है' में निभाए गए निकहत अहमद खान के किरदार के लिए जाना जाता है। इस धारावाहिक में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसी भूमिका ने उन्हें टेलीविजन की दुनिया में व्यापक पहचान दिलाने में मदद की।

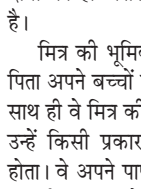


अर्चना तायडे
जन्म : 6 नवंबर 1988

अर्चना ने अपने करियर की शुरुआत मनोरंजन जगत में रियलिटी शो 'बॉलीवुड का टिकट' के माध्यम से की थी। इस शो में भाग लेने के बाद उन्हें अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले। धीरे-धीरे उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में अपनी जगह बनाई और कई प्रमुख चैनलों के कार्यक्रमों में काम किया। उनके करियर में सोनी टीवी, इमेजिन टीवी और 9एक्स जैसे बड़े मनोरंजन नेटवर्क के शो भी शामिल रहे हैं। अलग-अलग धारावाहिकों में काम करने के दौरान उन्होंने विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाईं और अपने अभिनय अनुभव को आगे बढ़ाया।

अर्चना तायडे का निजी जीवन भी मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वर्ष 2013 में अभिनेता आशीष शर्मा के साथ विवाह किया। आशीष शर्मा भी टेलीविजन और अभिनय की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा हैं। दोनों की जोड़ी को मनोरंजन जगत में खास पहचान मिली है। अर्चना ने अपने पेशेवर जीवन के साथ निजी जीवन को भी संतुलित रखा है।

छोटे पर्दे पर काम करने वाली अभिनेत्रियों में अर्चना तायडे की पहचान उनके अभिनय और टेलीविजन से जुड़े अनुभव के कारण बनी है। 'कुबूल है' में निकहत के किरदार ने उनके करियर को एक महत्वपूर्ण पहचान दी। रियलिटी शो से शुरुआत कर प्रमुख टेलीविजन चैनलों तक पहुंचने का उनका सफर मनोरंजन जगत में उनकी निरंतर सक्रियता को दर्शाता है।



कविता

दीवाली

रवि कुमार, मैहरी कांथला
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

भारतीय संस्कृति
की कुबेरनिधि है
दीवाली,
विजयश्री के
आंगन की तुलसी है
दीवाली ।
ममतारत उत्सुकता के
वर्ष में रसास्वादन
पर्व है दीवाली ।
स्नेहभाव सूचक
दुर्लभ संग्रहालय में,
सदविचारों,
आदर्शों की दिशा
सूचक है दीवाली ।
दिव्य ज्योति प्रकाश
पुंजों के सतरंगी दीपों
का चित्ताकर्षक
वार्षिक अधिवेशन है दीवाली ।
सुधामयी कोटि -
कोटि आकाशगंगा
में इन्द्रधनुषी
क्रीडांगना है
दीवाली,
साम्प्रदायिक सद्भावनामयी
विश्व में,
एक प्राचीन त्योहार है दीवाली ।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

भाजपा ने देव समाज प्रकोष्ठ की जिला और मंडल कार्यकारिणी की गठित

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। भारतीय जनता पार्टी के देव समाज प्रकोष्ठ की जिला एवं मंडल स्तर की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। जिला संयोजक सतीश लाल शर्मा ने पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर तथा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श के बाद नई नियुक्तियों की घोषणा की। जिला स्तर पर सोम देव मालपा और छेरिंग अंगरूप को सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, स्पीति मंडल में कलजंग सोनम को मंडल संयोजक तथा चेयरिंग अंगचुक और तेंजिन डोलताल को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। उदयपुर मंडल में छतर सिंह को संयोजक बनाया गया है, जबकि बचन सिंह और प्रकाश को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह केलांग मंडल में दिनेश को मंडल संयोजक तथा मनोज और नरेंद्र पॉल को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा के अनुसार इन नियुक्तियों का उद्देश्य देव समाज प्रकोष्ठ को जिला और मंडल स्तर पर मजबूत करना तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना है।

हिम अकादमी में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर हुआ विशेष मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, सुरेंद्र कटोच ,हमीरपुर। हिम अकादमी पब्लिक स्कूल, विकास नगर में द्वितीय अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की गई। इसमें अभिभावकों को प्रथम सत्र की परीक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करने के साथ विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और विशेष शिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बैठक में शिक्षकों ने विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धियों और सुधार की आवश्यकता वाले विषयों पर अभिभावकों से चर्चा की। विद्यालय में कक्षा तीसरी से बारहवीं तक विशेष शिक्षण व्यवस्था, ओलंपियाड परीक्षाओं और जेईई, नीट, एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षाओं, साप्ताहिक परिणाम विश्लेषण, अतिरिक्त कक्षाओं और करियर परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यार्थियों के नैतिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए 'सेवा' और 'मिशन प्रयास' जैसी पहल चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से अनुशासन, स्वच्छता, सद्व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी के संस्कार विकसित किए जा रहे हैं। अभिभावकों से घर पर भी बच्चों की दिनचर्या और व्यवहार पर ध्यान देने का आग्रह किया गया।

जनजातीय गौरव दिवस पर टोबा में स्वास्थ्य शिविर, 100 से अधिक लोगों की हुई जांच

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जिला योजना एवं जनजातीय विकास विभाग के तत्वावधान में आयुष विभाग ने वीरवार को ग्राम पंचायत टोबा में स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। आयुष विभाग के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित योगाभ्यास करने और विभिन्न बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही आयुष विभाग की योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में डॉ. अर्चना शारदा, डॉ. कुलदीप कुमार, डॉ. गगन दीप, विपिन कुमार, अशोक कुमार और योग प्रशिक्षक अवतार सिंह सहित पंचायत प्रधान हरजीत सिंह, वार्ड सदस्य दर्शाना देवी, ज्ञान चंद तथा वरिष्ठ नागरिक लाल चंद उपस्थित रहे।

अमित शाह और नड्डा से मिले भाजपा उपाध्यक्ष परमार

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक एवं सामाजिक हालात के साथ संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। परमार ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करवाया और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके बाद विपिन सिंह परमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं के साथ हुई मुलाकात को प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्र के पैसे से राजनीति चमका रहे मुख्यमंत्री सुक्खू : त्रिलोक कपूर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं और आर्थिक सहायता का श्रेय खुद लेकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर 'माल महाराज का, मिर्जा खेले होली' की कहावत सटीक बैठती है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कपूर ने प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की करीब 110 करोड़ रुपये की कथित लंबित देनदारी के कारण सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरों और जनसभाओं में सरकारी कर्मचारियों को बुलाने के लिए कथित प्रशासनिक दबाव बनाए जाने की निष्पक्ष जांच करवाने की भी मांग की। कपूर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं, राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विकास कार्यों का स्पष्ट रोडमैप जनता के सामने रखने की मांग की।

मतदाता जागरूकता के लिए बिलासपुर कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) की ओर से मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सदर के निर्देशानुसार 13 नवंबर को विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता होगी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल की अध्यक्षता में नायब तहसीलदार इलेक्शन नारायण दास के साथ हुई बैठक में आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें विधानसभा क्षेत्र-48 सदर बिलासपुर के विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के 33 चुनावी साक्षरता क्लब भाग लेंगे। इससे पहले 5 नवंबर को प्रो. अनुप्रिया की अगुवाई में आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता में 30 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष की आंचल प्रथम और रितिका कुमारी द्वितीय रहीं। प्रश्नोत्तरी में बीए द्वितीय वर्ष की श्रेयसी ने पहला और बीए तृतीय वर्ष की तृप्ता कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया। चारों विजेता छात्राओं ने मुख्य प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई है। 13 नवंबर को प्रत्येक वर्ग से 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं का सम्मान कर हमीरपुर को दिए दोनों शिक्षा बोर्डों के विकल्प

मेधावी विद्यार्थियों को वार्षिक समारोह में सम्मानित कर मेहनत और अनुशासन का दिया संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (एचपी बोर्ड), हमीरपुर का वार्षिक समारोह वीरवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश के अनेक सरकारी स्कूलों को सीबीएसई के अधीन लाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें। हमीरपुर शहर में भी पुराने ब्वायज स्कूल को सहशिक्षा संस्थान का दर्जा



देकर सीबीएसई के अधीन किया गया है।

उन्होंने कहा कि पुराने गर्ल्स स्कूल को प्रदेश के पहले समर्पित विज्ञान महाविद्यालय को सौंपने का प्रस्ताव था। हालांकि, इस संबंध में आम परिवारों के विद्यार्थियों, अभिभावकों, व्यापारियों और शहर के नागरिकों की भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए पुराने गर्ल्स स्कूल के स्थान पर एचपी बोर्ड के तहत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शुरू करने की तत्काल मंजूरी प्रदान की। इससे हमीरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सीबीएसई के साथ एचपी बोर्ड से पढ़ाई करने का विकल्प भी उपलब्ध हुआ है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से हमीरपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थान मिले हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज, उत्तर भारत के राज्यों का पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और प्रदेश का पहला समर्पित विज्ञान महाविद्यालय शामिल हैं। इन संस्थानों से हमीरपुर की पहचान मजबूत हुई है और स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिले हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने माता-पिता और शिक्षकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत, अनुशासन और लगन से पढ़ाई करें। शिक्षा के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही विद्यालय और समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

इससे पहले प्रधानाचार्य पूनम चौहान ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह को यादगार बनाया। समारोह में पूर्व पार्षद राजेश चौधरी, राकेश वर्मा, शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य दीप्ति राणा, कांग्रेस नेता राजेश आनंद, शहनशाह, मनोज शर्मा, आरसी डोगरा, ज्योति खन्ना, पुरुषोत्तम कालिया, टोनी ठाकुर, एसएमसी के पदाधिकारी, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हरप्रीत ने राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग में कांस्य जीतकर बढ़ाया हिमाचल का मान



◆ यूथ एशियन प्रतियोगिता में जगह भाटियां के हरप्रीत ने रचा नया कीर्तिमान

भारतेन्दु संवाददाता, नालागढ़। नालागढ़ की भाटियां पंचायत स्थित शिवालिक स्कूल पंजेहरा के खिलाड़ी हरप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। हरप्रीत ने अंडर-19 के 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 226 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन यूथ एशियन प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है।

हरप्रीत की उपलब्धि पर विधायक हरदीप सिंह बावा वीरवार को उसके घर पहुंचे और उसे सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ी को 11 हजार रुपये की नकद राशि दी। साथ ही भाटियां पंचायत में वेटलिफ्टिंग सेंटर खोलने के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है।

हरप्रीत के कोच मिथुन शर्मा ने बताया कि खिलाड़ी की उम्र अभी साढ़े 16 वर्ष है। वह अंडर-17 वर्ग में भी हिस्सा ले सकता था, लेकिन उसकी क्षमता को देखते हुए उसे अंडर-19 वर्ग में उतारा गया।

कोच के अनुसार भाटियां वेटलिफ्टिंग सेंटर के अन्य खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। अनामिका सैणी ने 48 किलो वर्ग में 117 किलो वजन उठाकर सातवां, पलासड़ा के करणजोत ने 79 किलो वर्ग में 235 किलो वजन उठाकर पांचवां और पीरस्थान की नित्या ठाकुर ने 98 किलो वर्ग में 247 किलो वजन उठाकर चौथा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबूराम, गुरिंद्र सैनी, हरप्रीत के पिता भूपेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

गुणवत्ता मानकों से वैश्विक बाजार में चमकेगा भारतीय इस्पात उद्योग

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में इस्पात क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई।



इसमें घरेलू इस्पात उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाने और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की बाजार में उपलब्धता रोकने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में इस्पात मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और नियामकीय बाधाओं को दूर करने पर विचार-विमर्श किया। इसका उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणियों के इस्पात उत्पादकों के लिए अनुपालन व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि इस्पात क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और घटिया गुणवत्ता वाले आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही घरेलू निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस्पात उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन जरूरी है। इससे देश की बढ़ती बुनियादी ढांचा संबंधी जरूरतों को स्वदेशी और भरोसेमंद इस्पात से पूरा किया जा सकेगा।

पुराने वीडियो को लेकर प्रवीन कुमार का पलटवार, उचित समय पर करेंगे बड़ा खुलासा

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने वर्ष 2017 के अपने पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर बार-बार वायरल किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की सोची-समझी कोशिश है। जिस व्यक्ति के इशारे पर यह अभियान चलाया जा रहा है, उसके कार्यकाल और कारनामों को उचित समय आने पर तथ्यों एवं सबूतों के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।

प्रवीन कुमार ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। इसे लेकर देश-प्रदेश और विदेशों में रहने वाले उनके शुभचिंतक लगातार फोन कर रहे हैं। विशेषकर युवा इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक लोगों के आग्रह पर अब उन्होंने इस मामले में अपनी बात रखने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वीडियो को काट-छांटकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार के चरणों में बैठने के दृश्यों को कमजोरी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। जबकि अपने राजनीतिक गुरु के चरणों में बैठना और उनसे मार्गदर्शन लेना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आगे भी उनका सम्मान करते रहेंगे।

पूर्व विधायक ने कहा कि वह भाजपा को अपनी मां मानते हैं और पार्टी के समक्ष अपनी बात रखने तथा न्याय की मांग करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में वह मजबूती से डटे रहेंगे और मैदान छोड़कर बैठने वाले नहीं हैं। प्रवीन कुमार ने कहा कि उनकी राजनीति का आधार भ्रष्टाचार या कारोबार नहीं, बल्कि जनता के बीच रहकर जनसेवा करना है। पालमपुर की जनता का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी असली पूंजी है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियानों से उनका हौसला कमजोर नहीं होगा और जनसेवा का संकल्प आगे भी कायम रहेगा।

सात महीने से बंद लगौटी स्वास्थ्य केंद्र, चार पंचायतें बेहाल

भारतेन्दु संवाददाता, धनेश गौतम, कुल्लू। क्षेत्र की चार पंचायतों के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगौटी पिछले सात महीनों से बंद पड़ा है। केंद्र के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। यहां न डॉक्टर उपलब्ध हैं और न ही मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था है। इसके चलते ग्रामीणों को छोटी बीमारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में भी करीब 40 किलोमीटर दूर आनी जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गंभीर मरीजों को उठानी पड़ रही है।



एडवोकेट रोहित साहसी ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरा है। उन्होंने कहा कि सात महीने से अस्पताल बंद रहना चार पंचायतों की जनता के साथ अन्याय है। ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी दूर जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे करती है।

उन्होंने मांग की कि लगौटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तुरंत खोला जाए और यहां डॉक्टर सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं की गईं तो क्षेत्रवासियों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

वहीं, वार्ड पंच रवि ठाकुर सहित क्षेत्र के युवाओं दिनेश ठाकुर, यशपाल यशु, ध्यान कटोच, नारायण कटोच, भीम ठाकुर और अन्य लोगों ने भी अस्पताल बंद होने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में 40 किलोमीटर दूर आनी पहुंचना मरीजों के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द स्वास्थ्य केंद्र खोलकर नियमित उपचार व्यवस्था शुरू करने की मांग की है।

नशा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा

घुमारवीं के दो आरोपी भेजे गए जबली जेल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई तेज करते हुए घुमारवीं क्षेत्र के दो आदतन आरोपियों को जबली स्थित मुक्त कारागार भेजा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत की कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी में लगातार संलिप्तता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान अश्वनी कुमार (35) निवासी बड्डू और पंकज कुमार (33) निवासी भदरे, तहसील घुमारवीं के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत पहले भी तीन-तीन मामले दर्ज हैं। बार-बार नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाने के चलते पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की।

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस



अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक हिरासत के आदेश जारी किए गए थे। निरोधक प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और दोनों को जबली मुक्त कारागार में दाखिल करवाया। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार युवाओं को नशे से बचाने और नशा तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी नशे के कारोबार से संबंधित जानकारी पुलिस के साथ साझा करने की अपील की गई है।

लंबित मामलों के निपटारे संग आपदा प्रभावितों को जल्द मिलेगी तीसरी किस्त

छह माह से लंबित राजस्व मामलों पर सख्ती विशेष अदालतों में होगी प्राथमिकता से सुनवाई

भारतेन्दु संवाददाता, अमर सिंह ठाकुर, बिलासपुर। उपायुक्त किरण भड़ाना ने राजस्व अधिकारियों को छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष राजस्व अदालतों के आयोजन में तेजी लाई जाए। वह बुधवार को बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने सीमांकन, बंदोबस्त, राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार, भू-अभिलेखों के अद्यतन, भू-अर्जन, भूमि बंटवारे और खाता विभाजन सहित विभिन्न राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित और समयबद्ध निपटारा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।



ये मामले आम लोगों के भूमि संबंधी अधिकारों और हितों से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे में इनके समाधान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन सुनिश्चित करने और छह माह से पुराने मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एसडीएम को अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित मामलों के निपटारे की व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व सेवाओं में जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपने काम करवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में उपायुक्त ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि जारी करने की प्रगति की भी समीक्षा की।

दीपावली पर घुमारवीं कॉलेज में सजी रंगों की आकर्षक रंगोलियां

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की रोवर एवं रेंजर इकाई की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय की सात टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों और आकर्षक डिजाइनों के माध्यम से सुंदर रंगोलियां बनाईं। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के प्रति रुचि विकसित करना था। प्रतियोगिता में टीम संख्या दो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस टीम में कुमकुम, रमन और रजनी शामिल रहे। वहीं, द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से टीम संख्या चार और पांच को मिला। टीम चार में कोमल ज्योत, किरण और अंकुश तथा टीम पांच में कशिश, कनिका और शगुन शामिल रहीं।

दीपावली पर प्रदेश के 1444 श्रमिक परिवारों को मिलेगी आर्थिक सौगात



भारतेन्दु संवाददाता,अनिल कुमार, हमीरपुर। दीपावली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड प्रदेश के 1444 पंजीकृत श्रमिक परिवारों को 6.10 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू छह नवंबर को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे।

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि यह आर्थिक सहायता श्रमिक परिवारों के लिए दीपावली का विशेष उपहार होगी। उन्होंने बताया कि विवाह सहायता योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपये, शिक्षा सहायता योजना के तहत 3.14 करोड़ रुपये और चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के अंतर्गत 32.80 लाख रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 86.58 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे। अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी 5.10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। जिलावार आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर के 148 लाभार्थियों को 64.94 लाख रुपये मिलेंगे। मंडी के 440 श्रमिक परिवारों को 1.61 करोड़, ऊना के 142 लाभार्थियों को 1.05 करोड़, शिमला के 183 को 72.97 लाख और बिलासपुर के 173 लाभार्थियों को 65.53 लाख रुपये दिए जाएंगे। किन्नौर के 168 लाभार्थियों को 64.92 लाख तथा कांगड़ा के 63 को 31 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सिरमौर, चंबा, कुल्लू और सोलन के श्रमिक परिवारों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

सहकारिता स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलेगा उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर

धर्मपुर-कुमारहट्टी में 29 नवंबर को होगा भाजपा का सहकारिता सम्मेलन

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ जिला सोलन की बैठक बुधवार को शहर के होटल गोल्डन बैंचर्स में जिला संयोजक यशपाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ 29 नवंबर को धर्मपुर-कुमारहट्टी में होने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र स्तरीय विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में भाजपा के समस्त प्रकोष्ठों के संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं जिला शिमला कोऑपरेटिव के चेयरमैन नरेश चौहान विशेष अतिथि तथा प्रो. रवीन्द्र ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में जिला सोलन के 13 मंडलों में





से आठ मंडलों के संयोजकों और सह-संयोजकों ने भाग लेकर आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए।

पुरुषोत्तम गुलेरिया ने राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को धर्मपुर-कुमारहट्टी में शिमला संसदीय क्षेत्र स्तरीय विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नवंबर माह का अंतिम रविवार होने के कारण कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को भी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से सुनेंगे। इससे कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री के विचार सुनने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की

एसआईआर पर कांग्रेस ने फैलाया भ्रम : नायब सैनी

विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष को घेरा, मुख्यमंत्री बोले- कांग्रेस ने खड़ा किया झूठ का गुब्बारा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

करनाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश में भ्रम और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर के मुद्दे पर झूठ का गुब्बारा खड़ा करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, जबकि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसी भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करने और भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हरियाणा पहुंचे हैं।

वीरवार को करनाल में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमित शाह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि देश में लंबे समय से मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। कांग्रेस इस प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है और लोगों के बीच गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रही है।



तथ्यों से विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देंगे भाजपा कार्यकर्ता।

मुख्यमंत्री ने एसआईआर के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1957 और 1967 सहित अलग-अलग समय पर मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जाता रहा है। वर्ष 2002 और 2004 में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का विरोध समझ से परे है।

कांग्रेस राजनीतिक हित साधने में जुटी : सैनी

सैनी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर मतदाता सूचियों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में एसआईआर को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर अपना हित साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की धरती से कांग्रेस के इस कथित भ्रामक प्रचार का जवाब देंगे। वह कार्यकर्ताओं को भी इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे, ताकि वे जनता के बीच जाकर एसआईआर की प्रक्रिया और उससे जुड़े तथ्यों को स्पष्ट कर सकें। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यों के आधार पर जवाब देने का आह्वान किया।

रेवाड़ी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, 500 से अधिक घाटों पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता के महापर्व छठ पूजा को लेकर रेवाड़ी में तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्वांचल और बिहार मूल के लोगों के प्रमुख त्योहार को भव्य रूप देने के लिए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने घाटों को तैयार करना शुरू कर दिया है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थायी और कृत्रिम छठ घाट बनाए जा रहे हैं। रेवाड़ी, धारूहेड़ा, भिवाड़ी और बावल सहित विभिन्न स्थानों पर करीब 500 घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां हजारों श्रद्धालु छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना करेंगे।

पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से कोनसीवास रोड स्थित श्याम वाटिका के सामने छठ घाट का निर्माण कराया गया है। समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि घाट तैयार करने के साथ आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। घाट के आसपास स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं



◆छठ महापर्व के रंग में रंगेगा रेवाड़ी, घाटों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन में शहर और आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। 15 नवंबर को दोपहर तीन बजे से अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को सुबह चार बजे से उगते सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। कृत्रिम घाटों का निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि एक बार में 250 से अधिक श्रद्धालु खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकें। सेक्टर एक स्थित सोलहराही तालाब में भी पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महाराणा प्रताप चौक से पूजा स्थल तक सजावट और बिजली की रोशनी लगाने का काम चल रहा है।

हरियाणा में स्मॉग का कहर, छह जिलों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर

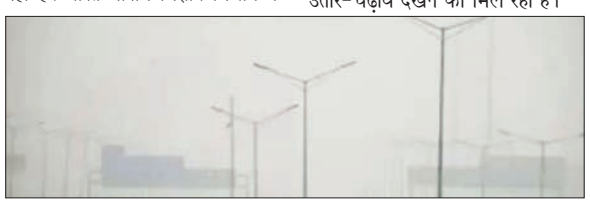
भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा में स्मॉग के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रदेश के छह जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया, जहां एक्यूआई 365 तक पहुंच गया। इसके अलावा प्रदेश के नौ जिले खराब वायु गुणवत्ता की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार वातावरण में मौजूद धुएं और धूल के कण नमी के संपर्क में आने से स्मॉग की स्थिति बन रही है। इसके कारण सुबह और शाम के समय हवा की गुणवत्ता अधिक खराब हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन दिनों तापमान में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

◆ छह जिलों का एक्यूआई 300 पार

लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल

प्रदूषित हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। दोपहर तक कई लोग आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। हवा में धूल और धुएं के कणों की अधिकता के कारण वातावरण में धुंध छाई हुई है। छह जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर पहुंचना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं, बहादुरगढ़ का 365 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर रहना चिंता का विषय बना हुआ है। मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है।



मनोहर लाल ने कांग्रेस की दिल्ली रैली को बताया फ्लॉप

कांग्रेस के झूठ से जनता परेशान: मनोहर लाल

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के पास न तो जनता के बीच उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा है और न ही लोगों का विश्वास बचा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस लगातार झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता उसकी वास्तविकता समझ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित रैली को भी फ्लॉप करार देते हुए कहा कि इसमें पार्टी को अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला।

मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और हरियाणा में सुशासन, विकास तथा जनकल्याण को प्राथमिकता देकर जनता का विश्वास हासिल किया है। सरकार की नीतियों का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। यही वजह है कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच अपने काम और उपलब्धियों के आधार पर जा रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह गई है।



बोले, कांग्रेस के पास न मुद्दा, न जनता का विश्वास।

वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस विषय को लेकर लगातार झूठ फैलाने और जनता में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकालेंगे और लोगों के सामने वास्तविकता रखेंगे। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है।

करनाल की मंडियों में उठान ने पकड़ी रफ्तार एक दिन में 15,654 मीट्रिक टन धान उठा

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक कम होने के साथ ही उठान कार्य में तेजी आने लगी है। बुधवार को पिछले एक सप्ताह के दौरान सबसे अधिक 15,654 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया। इससे मंडियों में जमा धान के ढेर कम होने लगे हैं और शेड भी खाली होने लगे हैं। इससे किसानों और आढ़तियों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, अभी भी मंडियों में बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है, जिसका उठान किया जाना बाकी है।

आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर को एक सप्ताह के दौरान सबसे कम 10,577 मीट्रिक टन धान का उठान हुआ था। इसके मुकाबले बुधवार को उठान में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल जिले की मंडियों में करीब 98,543 मीट्रिक टन धान उठान के इंतजार में पड़ा है। वहीं, इस सीजन में अब तक मंडियों से कुल 4.66 लाख मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।

डीएफएससी जनित मित्तल ने बताया कि मंडियों में धान की आवक का दबाव कम होने से खरीद एजेंसियों को उठान के लिए अधिक समय मिल रहा है। पहले मंडियों में धान के ढेर लगे होने और शेड पूरी तरह भरे रहने के कारण किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब उठान की गति बढ़ने से मंडियों में जगह खाली होने लगी है और व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट ठेकेदार को खरीदे गए धान का जल्द उठान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कार्य में तेजी आई है। खरीद एजेंसियों का दावा है कि यदि मौजूदा गति बनी रहती है तो अगले चार से पांच दिनों में मंडियों में बचे धान का उठान पूरा किया जा सकता है।

◆मंडियों में धान की आवक घटी तो उठान ने पकड़ी तेजी, अब 98,543 मीट्रिक टन बाकी

करनाल की अनाज मंडियों को मिली राहत

इससे मंडियों में पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी और आगामी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, तय समय में शेष धान का उठान पूरा करना खरीद एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। मंडियों में अभी मौजूद करीब 98,543 मीट्रिक टन धान की निकासी के लिए लगातार काम करना होगा।

अधिकारियों का कहना है कि उठान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसानों और आढ़तियों को अनावश्यक परेशानी न हो।

बिना अनुमति पटाखों का भंडारण करने वालों पर शिकंजा

पटाखों का अवैध भंडार पकड़ा, तीन गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को कई क्षेत्रों में छापेमारी कर पटाखों का अवैध जखीरा बरामद किया। इस कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद अवैध रूप से पटाखों का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस टीमों ने मुक्तिवाड़ा, तकियासराय, गोकलगेट और शक्तिनगर सहित विभिन्न इलाकों में संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान ऐसे लोगों को निशाने पर लिया गया, जो बिना अनुमति पटाखों की बिक्री और उनका भंडारण कर रहे थे। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से पटाखों का स्टॉक बरामद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया।

कार्रवाई के दौरान पकड़े गए तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद पटाखे कहां से लाए गए थे और इन्हें किन स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। इसके अलावा अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, इस मामले में शहर थाना और मॉडल टाउन थाना पुलिस की ओर से अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक की बेटी की शादी में वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा

भारतेन्दु संवाददाता,चंडीगढ़

यमुनानगर। कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज हुसैन की शादी का भव्य समारोह पांच नवंबर को यमुनानगर में आयोजित किया जा रहा है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए लक्कड़ मंडी मानकपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। समारोह के लिए करीब तीन एकड़ जमीन में भव्य पंडाल सजाया गया है। इसमें मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके खाने-पीने और बैठने तक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोजन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेहमानों की आवभगत के लिए 500 से अधिक वेटर तैनात किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोजन में 10 हजार से ज्यादा मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। इतने बड़े स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए व्यवस्थाओं को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, ताकि मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। समारोह के लिए उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से तैयार करवाकर पंडाल मंगवाया गया है। इसकी सजावट और व्यवस्था को भव्य स्वरूप दिया गया है। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों के लिए चार अलग-अलग वीआईपी केबिन भी बनाए गए हैं।

आयोजकों की ओर से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। वहीं, खाने-पीने की जिम्मेदारी अनुभवी हलवाई रमेश कुमार को सौंपी गई है। रमेश कुमार बड़े आयोजनों और वीआईपी समारोहों में भोजन तैयार करने का अनुभव रखते हैं। वह जिले में पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित कई प्रमुख आयोजनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।



◆तीन एकड़ में सजा पंडाल, 500 वेटर संभालेंगे मेहमान

घरेलू सामान खरीदने आई महिला से लूट

पानीपत में दो महिलाओं ने रुमाल सुंघाकर महिला को किया बेसुध

भारतेन्दु संवाददाता,चंडीगढ़

शहर के सलारगंज गेट के पास दो अज्ञात महिलाओं द्वारा एक महिला को बातचीत में उलझाकर कथित तौर पर रुमाल सुंघाकर बेसुध करने और उसके सोने के गहने व नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपित महिलाएं वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को लालबत्ती चौक तक ले गईं। कुछ समय बाद जब महिला को होश आया तो उसके गले से सोने की चेन, कानों से बालियां और पर्स में रखी नकदी गायब थी। पीड़िता की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव बड़ौली निवासी शीला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दो नवंबर को घरेलू सामान खरीदने के लिए पानीपत आई थी। दोपहर करीब चार बजे वह सलारगंज गेट के पास पहुंची थी। इसी दौरान वहां दो अज्ञात महिलाएं उसके पास आईं और उससे बातचीत करने लगीं। शुरुआत में सामान्य बातचीत के बाद दोनों महिलाओं ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया। आरोप है कि इसी दौरान उनमें से एक महिला ने उसके मुंह पर रुमाल लगा दिया, जिसके बाद वह बेसुध हो गई।

पीड़िता के अनुसार, इसके बाद दोनों महिलाएं उसे लालबत्ती चौक तक ले गईं। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामान की जांच की। इस दौरान उसके गले से करीब ढाई तोले की सोने की चेन और कानों से लगभग छह ग्राम वजन की सोने की बालियां गायब मिलीं। इसके अलावा उसके पर्स में रखे 10 से 15 हजार रुपये भी नहीं थे। अचानक हुई इस घटना से महिला परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है।

शीला देवी ने बताया कि होश आने पर उसके पास एक बंद बंडल मिला था। उसने उस बंडल को अपने पास रखने के बजाय पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता ने आरोपित महिलाओं की पहचान करने और उनसे चोरी किए गए गहने व नकदी बरामद करवाने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, दोनों महिलाएं वारदात के बाद मौके से फरार हो गई थीं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह घरेलू सामान खरीदने के उद्देश्य से शहर आई थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ यह घटना हो गई। अब पुलिस आरोपित महिलाओं का पता लगाने में जुटी है।

थाना शहर पुलिस ने शीला देवी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और अन्य जानकारियां जुटाने के आधार पर आरोपित महिलाओं की पहचान करने का प्रयास किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। □□ानबियों से बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।

पेंशन नहीं देने पर पंचकूला निगम अधिकारियों को अवमानना नोटिस

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। करीब 37 वर्ष तक सरकारी सेवा देने के बावजूद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए संघर्ष कर रहे नगर निगम पंचकूला के पूर्व कर्मचारी कृष्ण कुमार को अब तक राहत नहीं मिली है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि 14 सितंबर 2026 को दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई। कृष्ण कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता सजल बंसल ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ निर्धारित समयसीमा में जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद पूर्व कर्मचारी को अब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय तक सरकारी सेवा देने के बाद भी अपने वैधानिक लाभों के लिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

◆ 37 साल सेवा के बाद भी पेंशन को तरसे पूर्व कर्मचारी

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि निगम की ओर से पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद आदेश पर अमल नहीं किया गया। इससे पूर्व कर्मचारी को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि अदालत के निर्देशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले में नगर निगम की ओर से 15 दिनों के भीतर पेंशन के संबंध में निर्णय लेने और आठ सप्ताह में अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर फैसला करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विरोध | मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर कर्मवीर बौद्ध ने उठाए सवाल

कैथल में कांग्रेस का वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल

कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत गुरुवार को कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रा'यसभा सदस्य एवं कैथल के पर्यवेक्षक कर्मवीर बौद्ध ने शिरकत की। उनके साथ गुहला-चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस और जिला कांग्रेस कमेटी कैथल के अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में लोकतांत्रिक व्यवस्था, मताधिकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

कर्मवीर बौद्ध ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम नागरिकों के मताधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी का मुद्दा लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तथा निष्पक्ष रहे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बौद्ध ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है।



भाजपा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर करने का आरोप।

उन्होंने कहा कि 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट करना है। कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को उठा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कैथल के अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

मां की मौत के बाद नवजात की कस्टडी पर दो परिवारों में विवाद, 20 हजार में सौंपा बच्चा

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। शहर की सैनी कॉलोनी में एक महिला की मौत के बाद उसके नवजात बेटे की देखभाल और कस्टडी को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। मामला उस समय बढ़ गया, जब बिहार से पहुंचे महिला के ससुराल पक्ष के लोग नवजात को अपने साथ ले जाने लगे। वहीं, पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने बच्चे को अपने पास रखने की इच्छा जताते हुए उसे सौंपने से इन्कार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया।

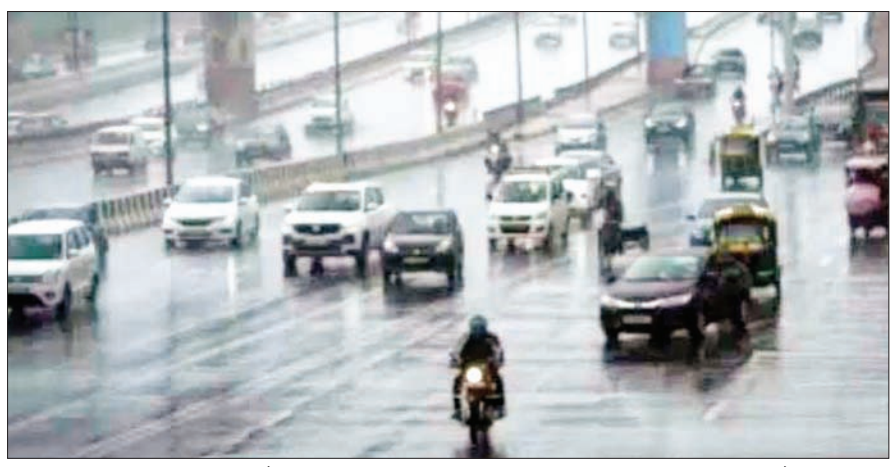
जानकारी के अनुसार, महिला की तबीयत खराब होने पर पड़ोसी परिवार ने उसके इलाज में मदद की थी। पड़ोसी परिवार का दावा था कि उन्होंने महिला के उपचार पर करीब 70 हजार रुपये खर्च किए हैं। परिवार में कोई बच्चा नहीं होने के कारण वे नवजात को अपने पास रखना चाहते थे। महिला की मौत के बाद उन्होंने बच्चे की देखभाल करने की इच्छा जताई और उसे अपने पास रखने की बात कही। दूसरी ओर, बिहार से पहुंचे महिला के ससुराल पक्ष के स्वजन बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे।

दोनों परिवारों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर सहमति नहीं बन पाई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत पड़ोसी परिवार को 20 हजार रुपये दिए गए, जिसके बाद उन्होंने नवजात को उसके स्वजन के हवाले कर दिया। इस तरह पुलिस की मध्यस्थता से बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हुआ और नवजात अपने स्वजन के साथ चला गया। घटना के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

◆इलाज पर 70 हजार खर्च करने का दावा, पड़ोसी परिवार ने मांगा नवजात का साथ

दिल्ली-एनसीआर में मौसम रहेगा साफ

दक्षिण भारत में चक्रवाती परिसंचरण का असर, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी



◆दिल्ली में सुबह छाएगी हल्की धुंध

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में जहां आसमान साफ रहने के साथ हल्की ठंड बढ़ने के आसार हैं, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले चार से छह दिनों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार से रविवार तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना दबाव कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण निचले वायुमंडल में सक्रिय है। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ और अन्य चक्रवाती परिसंचरण भी बने हुए हैं। इनके प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छह तथा नौ से 11 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है। सात और आठ नवंबर को यहां व्यापक बारिश का अनुमान है। छह से 11 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, केरल और माहे में भी छह से 11 नवंबर तक कई जगह बारिश होने के आसार हैं।

दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश

कर्नाटक और तेलंगाना में छह और सात नवंबर को बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आठ से 11 नवंबर तक व्यापक बारिश हो सकती है। यहां नौ से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छह से 11 नवंबर तक बारिश होने का अनुमान है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में नौ से 11 नवंबर के बीच भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आठ से 11 नवंबर के बीच छिटपुट बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

ग्रेटर नोएडा में मिठाई दुकानों पर छापेमारी, दो के लाइसेंस निलंबित

भारतेन्दु संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में त्योहारों के दौरान बाजारों में बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। दीपावली के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान मिठाई की दुकानों और निर्माण स्थलों पर कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार होती मिलीं तो कहीं घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल पाया गया। कुछ स्थानों पर मिठाई बनाने की परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि वे लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकती थीं। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान अब तक नियमों की अनदेखी करने वाले 20 दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं, गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई, वहां मिठाई निर्माण के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही उत्पादन में भी तेजी आती है, लेकिन इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है।

धनतेरस से पहले सोनीपत में वाहन बाजार चमका, 1000 गाड़ियां बिकीं



भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। सोनीपत। दीपावली और धनतेरस के त्योहार ने सोनीपत के वाहन बाजार में रौनक बढ़ा दी है। त्योहारों के चलते जिले में वाहनों की खरीदारी में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहनों तक की मांग में तेजी आई है। जिलेभर में अब तक 1000 से अधिक वाहन बिक चुके हैं। वहीं, विभिन्न कंपनियों के शोरूमों में ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के बीच कारों की एडवांस बुकिंग भी तेज हो गई है।

मारुति, टाटा, हुंडई, टोयोटा और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों के शोरूमों में करीब 300 कारों की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस पर नया वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी परंपरा के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने धनतेरस के दिन वाहन की डिलीवरी लेने के लिए पहले ही बुकिंग करवा ली है। कई ग्राहक अपनी पसंद के मॉडल और रंग का चयन भी पहले ही कर चुके हैं।

त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहन कंपनियों और शोरूम संचालकों ने भी विशेष तैयारियां की हैं। बुकिंग के अनुसार ग्राहकों को समय पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। कंपनियां ग्राहकों की पसंद और मांग को ध्यान में रखते हुए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी हैं। इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली के दौरान वाहन बिक्री के आंकड़ों में और इजाफा होगा।

कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले गढ़मुक्तेश्वर की सड़कों का चौड़ीकरण शुरू, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत



◆कार्तिक मेले से पहले बदलेगी गढ़मुक्तेश्वर की सड़कों की सूरत

भारतेन्दु संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले गढ़मुक्तेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मार्गों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यों के पूरा होने से इस वर्ष मेले में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सड़कों की स्थिति सुधरने से जाम की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार मेला शुरू होने से पहले ही सड़क सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है।

मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गढ़मुक्तेश्वर-मेरठ मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा मेला मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण और टाइल्स लगाने का कार्य भी कराया जा रहा है। स्याना फाटक और गढ़-मेरठ मार्ग पर भी सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इन मार्गों के बेहतर होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और श्रद्धालुओं को गड्ढों के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। प्रशासन का प्रयास है कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के गंगा घाटों तक पहुंच सकें।

मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में मौत

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ड्यूटी करने जा रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा गुरुवार सुबह गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हुआ। मृतक की पहचान 29 वर्षीय प्रभात शर्मा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र की गांधी कॉलोनी के निवासी थे और गाजियाबाद पुलिस लाइन में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे।

◆अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सिपाही को मारी टक्कर, मौत

जानकारी के अनुसार, प्रभात शर्मा को गुरुवार को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। वह बाइक से कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रभात शर्मा ने वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा शुरू की थी। नौकरी के शुरुआती दौर में ही इस हादसे ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में भी शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और फरार चालक का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

जवाद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब तलब

कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी ने मांगी सात दिन की अंतरिम जमानत



◆पत्नी का 8 नवंबर को टेस्ट और 10 नवंबर को कीमोथेरेपी

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली

अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने जांच एजेंसी को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है। जवाद अहमद ने अपनी याचिका में पत्नी की गंभीर बीमारी और उनके उपचार के लिए निर्धारित चिकित्सा प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया है।

याचिका के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी की पत्नी का आठ नवंबर को मेडिकल टेस्ट होना है, जबकि 10 नवंबर को उनकी कीमोथेरेपी निर्धारित है। ऐसे में उन्होंने पत्नी के इलाज और देखभाल के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत देने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि पत्नी के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण चिकित्सकीय प्रक्रियाएं आगामी दिनों में होनी हैं। इसी आधार पर जवाद ने अदालत से अस्थायी राहत देने की अपील की है, ताकि वह इस दौरान पत्नी के साथ रहकर उनके इलाज में सहयोग कर सकें।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जवाद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया है। अब अगली सुनवाई में ईडी की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

जवाद अहमद सिद्दीकी की याचिका पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। सात दिन की राहत देने या याचिका खारिज करने का निर्णय अगली सुनवाई के दौरान लिया जा सकता है। पत्नी की आठ नवंबर को होने वाली जांच और 10 नवंबर की कीमोथेरेपी को देखते हुए मामले में समय का विशेष महत्व है। ऐसे में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि जवाद अहमद को पत्नी के उपचार के दौरान उनके साथ रहने के लिए अस्थायी राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल ईडी का जवाब और अदालत की आगे की कार्यवाही इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे महंगे आईफोन-16 गिफ्ट



भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली के अवसर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस और तरह-तरह के उपहार देती हैं। लेकिन दिल्ली की एक कंपनी ने इस बार अपने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया है। राजधानी के रोहिणी स्थित इस कंपनी ने दीवाली गिफ्ट के रूप में अपने कर्मचारियों को आईफोन-16 भेंट किए हैं। करीब 70 हजार रुपये कीमत वाले इस महंगे उपहार को पाकर कर्मचारी काफी उत्साहित नजर आए।

कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिए गए इस विशेष उपहार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है। वीडियो में कर्मचारियों के लैपटॉप के सामने एक-एक आईफोन-16 रखा दिखाई दे रहा है। महिला कर्मचारी भी अपने हाथ में नया आईफोन दिखाते हुए खुशी जाहिर करती नजर आ रही हैं। कंपनी के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है? वहीं, दूसरे यूजर ने टिप्पणी की कि ऐसे वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को इतने महंगे उपहार मिलते देखकर जलन होने लगती है।

कंपनी के इस तोहफे ने कर्मचारियों के बीच दीवाली की खुशियां दोगुनी कर दीं। साथ ही यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

सुशासन और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देंगे दोनों संस्थान

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान और सुशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस (सीपीआरजी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। चार नवंबर को हुए इस समझौते का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को नीतिगत प्रक्रियाओं और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से नीति अनुसंधान, प्रभाव आकलन, विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में काम करेंगे। इसके साथ ही कार्यकारी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शोध आधारित प्रकाशनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माण से जुड़े लोगों को आपसी सहयोग के नए अवसर मिलेंगे। दोनों संस्थान डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार जैसे उभरते विषयों पर भी संयुक्त शोध करेंगे।

शेख सराय में बनेगी नई क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला

लंबित मामलों में 78.88 प्रतिशत की कमी से जांच व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली



◆151.80 करोड़ रुपए से राजधानी में वैज्ञानिक जांच का बढ़ेगा दायरा

राजधानी में आपराधिक मामलों की जांच को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए शेख सराय में नई क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (आरएफएसएल) स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण और स्थापना के लिए 151.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नई प्रयोगशाला के शुरू होने से रोहिणी स्थित मुख्य फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) पर काम का दबाव कम होगा। साथ ही दिल्ली में फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ने के साथ साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण में भी तेजी आएगी। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी।

गृह मंत्री ने कहा कि शेख सराय में स्थापित होने वाली नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला दिल्ली की मौजूदा एफएसएल की सहायक इकाई के रूप में काम करेगी। इससे जांच के लिए आने वाले मामलों का बेहतर तरीके से निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। एक साल पहले जहां जांच और परीक्षण के लिए लगभग 27 हजार मामले लंबित थे, वहीं अब इनकी संख्या घटकर करीब 5700 रह गई है। इस तरह लंबित मामलों में 78.88 प्रतिशत की कमी आई है।

आशीष सूद के अनुसार, यह उपलब्धि प्रशासनिक और परिचालन स्तर पर किए गए सुधारों का परिणाम है। सरकार फॉरेंसिक जांच व्यवस्था को आधुनिक बनाने और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके तहत नई विशेषज्ञ प्रयोगशालाएं स्थापित करने के साथ मौजूदा आधारभूत ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों, उन्नत मशीनों और डिजिटल तकनीक की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच अधिक सटीक और कम समय में की जा सके।

गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रयोगशाला की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनों के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एफएसएल में नियमित पदों और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है।

कृति सेनन की याचिका पर हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

◆प्रसिद्धि नहीं, हर व्यक्ति को पहचान के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कृति सेनन की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों और किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार अपने आप में कोई स्वतंत्र कानूनी आधार नहीं हैं और किसी व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करना मात्र गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी कृति सेनन की ओर से नाम, तस्वीर, हुलिए और आवाज के कथित दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए की।

कृति सेनन ने अपनी याचिका में पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने और अंतरिम राहत देने की मांग की थी। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किए जाने वाले डीपफेक वीडियो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनका रूप धारण करने और सिंथेटिक आवाज के इस्तेमाल जैसे मामलों का उल्लेख किया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक मूल्य की रक्षा करते हैं। ऐसे अधिकारों को लाइसेंस के माध्यम से किसी अन्य को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि निजता, गरिमा और प्रतिष्ठा जैसे व्यक्तिगत हित अलग प्रकृति के हैं। इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत अधिकार केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक मूल्य कितना है और उसके दुरुपयोग से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करते समय उसकी प्रसिद्धि एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। हालांकि प्रसिद्ध होना इन अधिकारों को प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त नहीं है।

प्रदूषणनियंत्रण नरेला से द्वारका तक धूल नियंत्रण अभियान तेज, हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी जोर

दिल्ली में प्रदूषण रोकने को डीडीए ने बढ़ाए इंतजाम

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली

21 लाख से अधिक पौधे लगाने का दावा



डीडीए के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में पार्कों, हरित क्षेत्रों और सड़कों के किनारे 21.24 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। पार्कों में 143 एकड़ के खाली और धूल भरे हिस्सों पर घास विकसित की गई है। करीब आठ किलोमीटर सड़क किनारे की जमीन पर भी घास और झाड़ियां लगाकर हरियाली बढ़ाई गई है। पार्कों में पेड़-पौधों की धुलाई और पैदल रास्तों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि सर्दियों के दौरान धूल नियंत्रण के लिए यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ निगरानी जारी रहेगी।

◆सड़कों की यांत्रिक सफाई और पौधारोपण से हवा सुधारने की पहल तेज

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज कर दिए हैं। इसके तहत नरेला में दो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की गई हैं, जबकि द्वारका में 270 मिस्टिंग पोल का नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन भी लगाई गई हैं।

डीडीए के अनुसार, ये सभी उपाय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की निगरानी में किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने धूल नियंत्रण के साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। चालू वित्त वर्ष में 21.24 लाख से अधिक पौधे लगाने और पार्कों में 143 एकड़ के धूल भरे हिस्सों पर घास विकसित करने का दावा किया गया है। इसके साथ ही खुले में कूड़ा जलाने, निर्माण मलबा डालने और निर्माण सामग्री को बिना ढके रखने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। डीडीए ने द्वारका में मिस्टिंग नेटवर्क का विस्तार कर इसकी कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर कर दी है। इस नेटवर्क में 270 पोल लगाए गए हैं। हाल ही में सेक्टर-8 में तीन किलोमीटर का नया हिस्सा शुरू किया गया है, जिसमें 66 पोल शामिल हैं। प्रत्येक पोल में 30 नोजल लगाए गए हैं। इनके माध्यम से सुबह सात से 11 बजे और शाम चार से आठ बजे के बीच हर घंटे 10 से 15 मिनट तक पानी का छिड़काव किया जाता है। इसका उद्देश्य हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करना है।

नरेला में 20 मीटर चौड़ी सड़कों की सफाई के लिए दो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें और धूल दबाने के लिए सात स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। वहीं, रोहिणी में 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के करीब 166 किलोमीटर हिस्से की एक दिन छोड़कर मशीनों से सफाई की जा रही है। इस अभियान में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सड़क किनारे के हिस्सों को भी शामिल किया गया है। यांत्रिक सफाई से सड़कों पर जमा धूल को हटाने में मदद मिल रही है।

दीपावली से पहले बाजारों में लौटी रौनक, बढ़ी खरीदारी

त्योहारी तैयारियों के बीच कपड़ों, सजावटी लाइटों और उपहारों की मांग तेजी से बढ़ी

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली



दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही उत्तरी बाहरी दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों को सजाने से लेकर नए कपड़े, मिठाइयां, उपहार और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। त्योहार की तैयारियों के चलते बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे दुकानदारों और कारोबारियों के चेहरों पर भी उत्साह दिखाई देने लगा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक खरीदारी का सिलसिला और तेज होगा तथा कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

पीतमपुरा, रोहिणी, प्रशांत विहार, अवंतिका, नरेला, बवाना, बादली, कमला नगर मार्केट और शालीमार बाग समेत क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। खासकर शाम के समय बाजारों में अधिक भीड़ देखने को मिली। लोग परिवार के साथ खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजारों में सजावटी सामान, कपड़ों, इलेक्ट्रानिक उत्पादों और उपहारों की दुकानों पर ग्राहकों की विशेष रुचि दिखाई दे रही है।

कारोबारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों तक बाजारों में ग्राहकों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, लेकिन अब खरीदारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। महीने की शुरुआत और वेतन मिलने के बाद बाजारों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि दीपावली के दौरान लोग घरों की जरूरतों के साथ त्योहार से जुड़ी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए भी खरीदारी करते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बाजारों में और अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है।

रोहिणी के विभिन्न सेक्टरों, पीतमपुरा और शालीमार बाग के बाजारों में घरों की सजावट से जुड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ी है। लोग रंग-बिरंगी लाइटें, झालर, बंदनवार, कृत्रिम फूल, सजावटी सामान और आकर्षक उपहार खरीद रहे हैं। दुकानों को भी दीपावली के मद्देनजर विशेष रूप से सजाया गया है, जिससे बाजारों में त्योहार जैसा माहौल बनने लगा है।

व्यापारी विपिन जैन ने बताया कि दीपावली पर नए कपड़े पहनने की परंपरा के चलते कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। महिलाएं साड़ी, सूट, कुर्ती और अन्य परिधानों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं युवाओं में फैशनेबल कपड़ों और बच्चों के लिए नए परिधानों की मांग बनी हुई है। उपहारों की दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। लोग अपने परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों को देने के लिए अलग-अलग तरह के उपहार पसंद कर रहे हैं।

अवंतिका मार्केट के प्रधान विजयपाल ने बताया कि दीपावली पर घरों और दुकानों को रोशनी से सजाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइटों की मांग बढ़ गई है। बाजार में एलईडी झालर, पर्दे वाली लाइटें, रंग-बिरंगी लड़ियां और अन्य सजावटी इलेक्ट्रिक उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ इनकी बिक्री में और तेजी आएगी।



जापान के राजदूत ओनो केईची ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

राज्य ब्यूरो

देहरादून। भारत में जापान के राजदूत ओनो केईची ने बुधवार को लोक भवन में उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर जापान दूतावास में थर्ड सेक्रेटरी काकुता नानामी भी उपस्थित रहीं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल और जापान के राजदूत के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी संवाद और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए। शिष्टाचार भेंट के बाद जापान के राजदूत ओनो केईची और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन परिसर स्थित बोनसाई गार्डन का भ्रमण किया। उन्होंने यहां संरक्षित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का अवलोकन किया और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। राजदूत ने बोनसाई गार्डन में पौधों की कलात्मक संरचना, उनकी सुंदरता और संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने गार्डन में विभिन्न आकारों और प्रजातियों के बोनसाई पौधों को आकर्षक बताया। इस अवसर पर लोक भवन परिसर की हरियाली और पौधों के व्यवस्थित संरक्षण को भी प्रतिनिधिमंडल ने सराहा। जापानी प्रतिनिधिमंडल का यह भ्रमण लोक भवन के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से परिचित होने का अवसर बना।

उत्तराखंड आंदोलन के नायकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता : धामी

धामी ने किया राज्य आंदोलनकारी रणजीत सिंह वर्मा पर पुस्तक का विमोचन

राज्य ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईआरडीटी सभागार, सर्वे चौक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी सेनानी एवं जननायक स्व. रणजीत सिंह वर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक 'रणजीत सिंह वर्मा : उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन की निर्णायक लड़ाई के एक जननायक' का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्व. वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन का इतिहास संघर्ष, त्याग, बलिदान और दृढ़ संकल्प की गाथा है। इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखन और प्रकाशन से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार गंभीर सिंह पालनी एवं अजय वर्मा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल एक जननायक की जीवनगाथा नहीं, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और संकल्प का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को राज्य निर्माण के इतिहास, आंदोलनकारियों के योगदान और उनके त्याग एवं बलिदान के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्व. रणजीत सिंह वर्मा ने पृथक उत्तराखंड की मांग को बुलंद करने और आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



◆राज्य निर्माण के संघर्ष और बलिदान का दस्तावेज बनी पुस्तक

धामी ने बताया कि स्व. वर्मा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के देहरादून जनपद अध्यक्ष रहे। उन्होंने विभिन्न संगठनों और आंदोलनकारियों को एक मंच पर लाकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की। वर्ष 1995-96 और उसके बाद भी उन्होंने देहरादून में आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। बंद, चक्का जाम, जेल भरो और रेल रोको जैसे आंदोलनों का नेतृत्व कर पृथक राज्य की मांग को मजबूती दी। उन्होंने डोईवाला के प्रेमनगर बाजार स्थित अपनी ससुराल को भी आंदोलन का केंद्र बनाया और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले आंदोलनकारियों के ठहरने की व्यवस्था में सहयोग किया।

देहरादून में आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा

धामी ने बताया कि स्व. वर्मा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के देहरादून जनपद अध्यक्ष रहे। उन्होंने विभिन्न संगठनों और आंदोलनकारियों को एक मंच पर लाकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की। वर्ष 1995-96 और उसके बाद भी उन्होंने देहरादून में आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। बंद, चक्का जाम, जेल भरो और रेल रोको जैसे आंदोलनों का नेतृत्व कर पृथक राज्य की मांग को मजबूती दी।

देहरादून में 'भैरव वाणी' पत्रिका और न्यूज पोर्टल का शुभारंभ



भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, धार्मिक विरासत, क्षेत्रीय सरोकारों और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के उद्देश्य से 'भैरव वाणी' पत्रिका एवं न्यूज पोर्टल का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रखर क्षेत्रीय संगठन भैरव सेना के तत्वावधान में हरिद्वार बाईपास रोड स्थित संगठन के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य ध्येय वाक्य 'सत्य, संस्कृति, संचार—देवभूमि उत्तराखंड की आवाज' रखा गया है। इस नए मीडिया मंच के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और सामाजिक गतिविधियों को प्रमुखता से सामने लाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निरंजनी अखाड़े के श्रीमहंत स्वामी दर्शन भारती उपस्थित रहे।

देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान

राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र बॉबी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी मंच मिलना आवश्यक है। 'भैरव वाणी' के मुख्य संपादक संदीप खत्री ने पोर्टल शुरू करने के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यह मंच जनसमस्याओं, क्षेत्रीय मुद्दों और धार्मिक विषयों को बेबाकी से उठाएगा।

शुभारंभ में संगठन के कई पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर भैरव सेना के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, केंद्रीय सचिव संजय पवार, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मयंक मलेठा और प्रदेश संगठन मंत्री गणेश जोशी सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक संस्था देवभूमि भैरव वाहिनी की कार्यकर्ता गोरी कोठियाल, गीता बिष्ट, सुनीता थापा और लक्ष्मी थापा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

चमोली में स्वयं सहायता समूहों ने सजाए दीपावली के स्टॉल

भारतेन्दु संवाददाता, चमोली। दीपावली के पर्व पर स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विकासखंड दशोली के हरियाली क्लस्टर, देवर खडोरा की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर गोपेश्वर में आकर्षक स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉलों पर महिलाओं द्वारा हाथों से तैयार किए गए पारंपरिक और सजावटी उत्पादों के साथ विभिन्न घरेलू उपयोग की वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

स्टॉलों में बजरंगबली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार आकर्षक दीपक और मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। वहीं, हिलांस और भवानी स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। देवभूमि स्वयं सहायता समूह की अंजू राणा सहित अन्य महिलाएं मिट्टी के दीये और घरेलू उपयोग की वस्तुएं लेकर पहुंची हैं। इन उत्पादों में स्थानीय कला, संस्कृति और महिलाओं की रचनात्मकता की झलक देखने को मिल रही है। ग्रामोत्थान परियोजना (रीप) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता विकास और विपणन के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाओं ने दिखाई हुनर और रचनात्मकता



स्टॉलों में बजरंगबली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार आकर्षक दीपक और मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। वहीं, हिलांस और भवानी स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। देवभूमि स्वयं सहायता समूह की अंजू राणा सहित अन्य महिलाएं मिट्टी के दीये और घरेलू उपयोग की वस्तुएं लेकर पहुंची हैं।

बर्फ में दबे मिले दो और शव

केदारताल हादसा : दो और शव मिले, तलाश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के केदारताल ट्रेक पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चपेट में आए आठ सदस्यीय दल के छह लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। गुरुवार को एसडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान दो और पुरुषों के शव बरामद किए। हालांकि, दोनों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम के कारण शवों को शुक्रवार को हेलीकॉप्टर की मदद से मातली हेलीपैड लाने की योजना है। इसके बाद उनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि बचाव दल ने हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले बुधवार सुबह मिले दो शवों की पहचान पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सालबनी निवासी रिंटू मंडल (40) और उदय घोष (30) के रूप में हुई थी। अब तक बरामद छह शवों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। इनमें से चार की पहचान हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर को सात ट्रेकर्स और पांच सहयोगी कर्मचारियों सहित 12 सदस्यीय दल केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चपेट में आने से आठ सदस्य लापता हो गए थे। शुरुआती बचाव अभियान में तीन पोर्टर और एक रसोइये सहित चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था।

क्या उत्तराखंड हादसों का राज्य बनता जा रहा है?

कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश, कहीं मोहब्बेवाला हाईवे पर मौत का तांडव, आखिर जवाबदेही किसकी?

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियों और सुरक्षित यात्राओं के लिए जाना जाता था, आज लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। कहीं चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों में जिंदगियां खत्म हो रही हैं, तो कहीं मोहब्बेवाला राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं परिवारों को उजाड़ रही हैं। लगातार हो रहे हादसों ने प्रदेश की यातायात और परिवहन व्यवस्था के साथ ही संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सवाल सिर्फ दुर्घटनाओं का नहीं है, सवाल उन व्यवस्थाओं का है जिन्हें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा और संचालन पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की भूमिका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों पर सुरक्षा मानकों, संकेतकों, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी कौन कर रहा है?

हादसों के बाद नहीं, पहले तय हो जिम्मेदारी



क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की जिम्मेदारी सिर्फ वाहनों के चालान और कागजी सत्यापन तक सीमित है या सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उसकी प्राथमिकता है? इन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है। हादसा होने के बाद निरीक्षण, बैठकें और जांच के निर्देश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन हादसे से पहले रोकथाम की व्यवस्था कहां है? मोहब्बेवाला राजमार्ग पर लगातार दुर्घटनाओं की चिंता हो या चारधाम हवाई सेवा में यात्रियों की सुरक्षा का सवाल, हर जगह एक ही प्रश्न सामने आता है कि जिम्मेदार विभाग अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे? दुर्घटनाओं के बाद जांच कराना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि पहले से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी कौन करेगा?

आखिर कब तक आम नागरिकों और यात्रियों को इस तरह की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब सड़क पर चलने वाला नागरिक और आसमान में उड़ने वाला यात्री सुरक्षित हो। सरकार से सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की जवाबदेही तय करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? दुर्घटना के बाद मुआवजा और जांच ही समाधान है या दुर्घटनाएं रोकने की भी कोई समयबद्ध नीति बनेगी? क्या संबंधित विभागों की नियमित निगरानी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा? देवभूमि को हादसों की पहचान नहीं, सुरक्षित यात्रा की मिसाल बनाइए। क्योंकि जनता को भाषण नहीं, सुरक्षा चाहिए और अधिकारियों से बहाने नहीं, जवाब चाहिए।

बांसुरी स्वराज बोलीं, मोदी-धामी के विकास कार्यों से भाजपा को मिलेगा जनसमर्थन

छह विधानसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा ने कसी कमर

भारतेन्दु संवाददाता, नई टिहरी। भाजपा की सह प्रदेश प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के दम पर उत्तराखंड में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर विरोध करने की राजनीति कर रहा है, जबकि उसके पास उत्तराखंड के विकास के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।



वीरवार को पहली बार टिहरी पहुंचीं बांसुरी स्वराज का जिलाध्यक्ष उदय रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा का मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए। बैठक में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने तथा जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया।

उत्तराखंड में पत्रकारों की सुविधाओं का होगा विस्तार : पुष्कर सिंह धामी

धामी की पत्रकारों को सौगात, बढ़ेगी मान्यता और पेंशन राशि



राज्य ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग कर पत्रकारों और प्रेस क्लब के सदस्यों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के हित में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश में तहसील, जिला और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पत्रकार पेंशन की राशि में भी वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के हितों, कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही उनकी कामना है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ ही समाज और सरकार के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्रकार आम जनता तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी पहुंचाने के साथ लोगों की समस्याओं और अपेक्षाओं को भी शासन तक पहुंचाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में पत्रकारों की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका महत्वपूर्ण है।

◆पत्रकार कल्याण कोष के लिए 10 करोड़

न्यूज ब्रीफ

पौड़ी में गुलदार के हमलों पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। खांड्यूंसैंड में गुलदार के हमले में पांच वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हुए धरना-प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस नेता विनोद दनोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पार्टी में नाराजगी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी और दनोसी ने वन विभाग की कार्रवाई को साजिश बताते हुए सवाल उठाए। दनोसी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान डीएफओ के साथ मारपीट नहीं हुई थी। ग्रामीण गुलदार के आतंक से निजात और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता सुंदर लाल मयाल ने बढ़ते पलायन, गुलदार के हमलों और अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

उत्तराखंड में सड़क, सिंचाई और मंदिरों के विकास को मिलेगी गति

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, सिंचाई, आवास, मंदिरों के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए 42.78 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें कुंभ मेला-2027 के अंतर्गत छह मार्गों के निर्माण के लिए 26.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में सड़क एवं पैदल मार्ग, टिहरी में मंदिरों के सौंदर्यीकरण, चम्पावत में सिंचाई गूल और धार्मिक स्थलों के विकास तथा उत्तरकाशी में आवास निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी सिंचाई एवं सड़क सुधारीकरण के कार्य होंगे। इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

स्वदेशी उत्पाद अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को दें मजबूती : धामी

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि धनतेरस आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है, जबकि दीपावली सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशहाली लाए। उन्होंने गोवर्धन पूजा को आर्थिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रतीक बताया। भैयादूज भाई-बहन के प्रेम और महिलाओं के सम्मान का पर्व है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाते हुए स्वदेशी उत्पाद खरीदने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की अपील की।

धनतेरस से भैयादूज तक हरिद्वार में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

भारतेन्दु संवाददाता, हरिद्वार। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज के त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक भारी वाहनों और कमर्शियल लोडिंग वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। ज्वालापुर, नगर कोतवाली, कनखल और रानीपुर क्षेत्र में अलग-अलग पार्किंग स्थल और बैरियर प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल से दुर्गा चौक, रेल चौकी, सेक्टर-2 और भगत सिंह चौक तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हरकी पैड़ी और खड़खड़ी क्षेत्र में भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। नगर कोतवाली क्षेत्र में सूखी नदी तिराहे से भीमगौड़ा बैरियर तक भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। कनखल में सिंहद्वार से जगजीतपुर तक कमर्शियल लोडिंग वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं, शिवालिकनगर में भी चिन्मय चौक से सलेमपुर चौक तक भारी और छोटे कमर्शियल वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। यातायात का दबाव बढ़ने पर विभिन्न मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू की जाएगी। पुलिस ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े नहीं करने की अपील की है।

शुरुआत पिथौरागढ़ के यक्षवती नदी क्षेत्र और हरिद्वार की पीली पड़ाव ग्राम पंचायत से अभियान शुरू

उत्तराखंड में दो माह चलेगा जल-कृषि समृद्धि अभियान

राज्य ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में जल संरक्षण, कृषि विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलागम विभाग की ओर से राज्यस्तरीय जल-कृषि समृद्धि अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान आगामी दो माह तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को गति देने के साथ ही आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही जल और कृषि संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा।



ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और कृषि संबंधी गतिविधियों को मिलेगी नई गति।

जलागम मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना, किसानों को बीज वितरित करना, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ गोष्ठियां आयोजित करना तथा जनजागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जल-कृषि समृद्धि अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, ग्रीन एजी (जैफ-6) परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलागम घटक 2.0 तथा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी (सारा) की विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने, वर्षा जल के बेहतर उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और किसानों की आजीविका को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि अभियान का शुभारंभ पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिले से हो चुका है। पिथौरागढ़ के यक्षवती नदी क्षेत्र में नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जनजागरूकता गतिविधियों, दिया दान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नदियों तथा जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी के जरिए जल संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व भी बताया गया।

वहीं, हरिद्वार की पीली पड़ाव ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसमें धान की सीधी बुवाई (डीएसआर), गोबर गैस संयंत्र और अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। ग्रामीणों को इन तकनीकों के उपयोग और उनके लाभों से भी अवगत कराया गया। जलागम विभाग का यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और जल एवं कृषि संसाधनों के संरक्षण के प्रति जनभागीदारी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अगले दो माह तक आयोजित होने वाली गतिविधियों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने और कृषि विकास से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।

रुद्रप्रयाग की बेटियों ने खेल मैदान में दिखाया दम, नौ स्वर्ण झटके

भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित स्कूल राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अगस्त्यमुनि छात्रावास की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल कौशल का परिचय देते हुए कुल 15 पदक हासिल किए। इनमें नौ स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं। बालिकाओं की इस उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी की लहर है। उनकी शानदार सफलता के पीछे नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथलेटिक्स प्रशिक्षक एवं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मनोज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए विशेष तैयारी की थी। जिला क्रीड़ा अधिकारी मनोज सिंह चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि छात्रावास की बालिकाओं के बढ़ते खेल स्तर और उनकी मेहनत का प्रमाण है।

न्यूज ब्रीफ

शैलजा शर्मा ने ऑल इंडिया एक्सीलेंसी वुमन अवार्ड-2026 में हासिल किया प्रथम स्थान



भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। मंडी जिले में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर कार्यरत शैलजा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिसेज यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया एक्सीलेंसी वुमन अवार्ड-2026 में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उनकी दूसरी बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। प्रसिद्ध 'डेवलिशियस' समूह के सौजन्य से आयोजित इस समारोह में देश के 20 से अधिक राज्यों की प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया। प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकारों के लिए निर्णायक मंडल ने शैलजा शर्मा को सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना। मूल रूप से पंचरुखी (पालमपुर) की रहने वाली शैलजा शर्मा प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के कार्यों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने इस सम्मान का श्रेय उन सभी महिलाओं को दिया, जो घर और कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। उन्होंने युवा महिलाओं से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उनकी उपलब्धि पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पालमपुर में जिला स्तरीय युवा संसद में तमन्ना, अक्षय और मनीषा ने मारी बाजी



भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। साई विश्वविद्यालय पालमपुर में 3 नवंबर को जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद व 'अपना वोट जानो' युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा युवा भारत (माई भारत), कांगड़ा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के पहले सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर युवा संसद आयोजित की गई। इसमें जिलेभर के युवाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल के मूल्यांकन में तमन्ना, अक्षय कुमार और मनीषा पठानिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। ये तीनों विजेता अब शिमला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कांगड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरे सत्र में 'अपना वोट जानो' विषय पर संवाद हुआ, जिसमें युवाओं को मतदान के अधिकार और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कांगड़ा-चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज मुख्यातिथि रहे। विधायक विपिन सिंह परमार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एसके पुंज, वीपी पाटिल और युवा प्रतिनिधि शाश्वत कपूर भी उपस्थित रहे। सांसद ने प्रतिभागियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की शपथ दिलाई।

रिवालसर कॉलेज में रोवर-रेंजर स्वयंसेवियों ने सीखीं स्काउटिंग की बारीकियां



भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। राजकीय महाविद्यालय रिवालसर की रोवर-रेंजर इकाई की ओर से स्वयंसेवियों के लिए स्काउटिंग की आधारभूत जानकारी और बेसिक गांठों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की गांठें बांधने और उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में रोवर स्काउट लीडर डॉ. कुलदीप कुमार, रेंजर लीडर डॉ. अंजली परमार और राष्ट्रपति स्काउट रोहित ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने गांठें बांधने की विधियों का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से अभ्यास भी करवाया। प्रशिक्षकों ने बताया कि टेंट लगाने, पायनियरिंग गतिविधियों और आपातकालीन बचाव कार्यों में इन तकनीकों का विशेष महत्व है। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वयंसेवियों को आगामी रोवर-रेंजर शिविर के लिए तैयार करना था। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ब्रज नंदन ने कहा कि स्काउटिंग विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने सराहा संफिया फाउंडेशन का 'थैरेपी ऑन व्हील्स' अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। स्पेशल ओलंपिक्स भारत, हिमाचल प्रदेश की ओर से सुंदरनगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल स्कूल, बीबीएमबी कॉलोनी के मैदान में 'दीपावली फेस्ट-2026' आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सम्फिया फाउंडेशन की 'थैरेपी ऑन व्हील्स' पहल की सराहना करते हुए दूरदराज के गांवों में दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक थेरेपी सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों को सराहनीय बताया। कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉ. मलिका नड्डा और बीबीएमबी सुंदरनगर के सदस्य (सिंचाई) इंजीनियर बीएस नारा विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता बीबीएमबी अध्यक्ष इंजीनियर मनोज त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर सम्फिया फाउंडेशन ने स्टॉल के माध्यम से अपनी गतिविधियों और सेवाओं की जानकारी दी। अभिभावकों और विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया। फाउंडेशन की 'थैरेपी ऑन व्हील्स' पहल का उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों और विशेष बच्चों को उनके घरों के नजदीक आवश्यक थेरेपी, मार्गदर्शन और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम में विशेष बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और समावेशी समाज के निर्माण पर भी जोर दिया गया।

अग्निवीरों को अतिरिक्त सेवा में मिलेगा बेहतर वेतन और वरिष्ठता का लाभ : रवि

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर देने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया यह निर्णय सशस्त्र बलों में सेवाएं दे रहे युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला अग्निवीरों के योगदान और भविष्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। रवि ठाकुर के अनुसार, चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत योग्यता और मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। वहीं, शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी इच्छा से दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। इसके बाद निर्धारित चयन मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीर नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को बेहतर पारिश्रमिक, उन्नत सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता संबंधी लाभ भी मिलेंगे। इससे युवाओं को सेना में अनुभव और कौशल बढ़ाने का अवसर मिलेगा। रवि ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के भविष्य के साथ-साथ भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक अनुभवी और सक्षम बनाने में भी सहायक होगा।



सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बैंक खाते की आधार सीडिंग करवाएं लाभार्थी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से अपने बैंक और डाकघर बचत खातों को आधार से सीड करवाने की अपील की है। विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि आधार सीडेड खातों में ही ऑनलाइन माध्यम से पेंशन जारी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों से भी प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर में जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल एवं आय प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पोर्टल *himparivar.hp.gov.in/ekalyan* पर अपलोड करने का आग्रह किया। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

नगरोटा बगवां में सबसे बड़ा सवाल... कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी तो बड़ोह की अनदेखी क्यों?

बड़ोह में सरकारी होटल खुला तो धार्मिक पर्यटन को लगेंगे पंख, नगरोटा बगवां से निहारगलू, छूघेरा व सरोत्री होते हुए बड़ोह तक एक अदद ढाबा या रेस्तरां तक नहीं

सन्नी महाजन, भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के सरकारी संकल्प के बीच नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र का बड़ोह एक ऐसी पर्यटन संभावनाओं वाला स्थल है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहा है। यहां स्थित ऐतिहासिक श्रीकृष्ण मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला देखने और भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने के लिए देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों को यहां तक पहुंचने के रास्ते में खाने-पीने की बुनियादी सुविधा तक नहीं मिलती।

नगरोटा बगवां से निहारगलू, छूघेरा, सरोत्री होते हुए बड़ोह तक के मार्ग पर न कोई ढाबा है, न रेस्तरां और न ही पर्यटकों की जरूरत के मुताबिक कोई ढंग का भोजनालय। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात कर रही है, तो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल को सुविधाओं से जोड़ने की योजना क्यों नहीं बन रही है? स्थानीय लोगों की मांग है कि नगरोटा बगवां से बड़ोह के बीच हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) का एक सरकारी होटल खोला जाए। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने तथा खानपान की सुविधा मिलेगी, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए रास्ते भी खुलेंगे। नगरोटा बगवां में एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली की देखरेख में करोड़ों रुपए की पर्यटन विकास योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि बड़ोह के ऐतिहासिक मंदिर को भी पर्यटन विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं, ग्रामीण क्षेत्र पीछे क्यों?

हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पर्यटन उद्योग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में करीब 7.78 प्रतिशत योगदान देता है। वर्ष 2025 में कांगड़ा जिले में 8.26 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि 2026 के शुरुआती छह महीनों में छह लाख से अधिक पर्यटकों के आने की खबर है। इसके बावजूद ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बड़ोह बुनियादी पर्यटक सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन राजधानी बनाने के दावों के बीच ग्रामीण पर्यटन स्थलों की अनदेखी हो रही है। नगरोटा बगवां से बड़ोह तक भोजनालय और पर्यटक सुविधा केंद्र का अभाव पर्यटन विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।



चंगर क्षेत्र की अनदेखी क्यों?

सबसे बड़ी बात यह है कि आरएस बाली नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। ऐसे में चंगर क्षेत्र के लोगों की उनसे उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं, जब कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात हो रही है, तो बड़ोह जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने में देरी क्यों हो रही है? स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या चंगर क्षेत्र को भी पर्यटन विकास की योजनाओं में बराबर की प्राथमिकता मिलेगी?

मुख्यमंत्री से हजारों लोगों की गुहार

क्षेत्र के लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि नगरोटा बगवां से बड़ोह के बीच एचपीटीडीसी का सरकारी होटल खोलने की योजना बनाई जाए। इसके लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित कर बजट का प्रावधान किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि सरकार इस दिशा में पहल करती है, तो बड़ोह मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने का रास्ता खुलेगा। इससे कांगड़ा की पर्यटन राजधानी की परिकल्पना को ग्रामीण स्तर पर भी सार्थक रूप दिया जा सकेगा।

बड़ोह मंदिर की धार्मिक व ऐतिहासिक पहचान को पर्यटन से जोड़ने की जरूरत : अर्चना कुमारी

सद्दूं पंचायत की प्रधान अर्चना कुमारी ने कहा कि नगरोटा बगवां में पर्यटन की ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिनका लाभ वास्तव में क्षेत्र की जनता को मिले। उन्होंने कहा कि बड़ोह मंदिर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है। मंदिर की अद्भुत नक्काशी और धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यदि सरकार मंदिर के आसपास एचपीटीडीसी का होटल खोलती है, तो यह क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा होगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

बड़ोह में होटल निर्माण से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर : बलविंद्र

ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जिला अध्यक्ष, नंबरदार, सहकारी सभा के प्रधान व समाजसेवी बलविंद्र सिंह बबलू ने कहा कि बड़ोह में सरकारी होटल खुलना धार्मिक पर्यटन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहां आने वाले पर्यटकों को ठहरने और खाने-पीने की सुविधा मिलेगी, तो वे आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों का भी रुख करेंगे। इससे क्षेत्र में कारोबार बढ़ेगा व स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार पर्यटन राजधानी के सपने को केवल बड़े शहरों व चुनिंदा पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी इसमें शामिल करे।

प्लास्टिक के सस्ते सामान ने छीनी पारंपरिक हस्तशिल्पियों की रोजी-रोटी, कुल्लू दशहरा मेले में फीका रहा कारोबार

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार पारंपरिक हस्तशिल्पियों को कारोबार के लिहाज से निराशा हाथ लगी है। दशहरा मैदान में हाथों से तैयार टोकरियों, किल्टों, लकड़ी के घरेलू औजारों और लोहे की वस्तुओं की दुकानें सजीं, लेकिन इन उत्पादों को उम्मीद के मुताबिक खरीदार नहीं मिले।

आधुनिक दौर में प्लास्टिक और मशीनों से तैयार सस्ते सामान की बढ़ती मांग ने पारंपरिक कारीगरों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। कारीगरों का कहना है कि हाथों से तैयार उत्पाद बनाने में काफी समय, मेहनत और हुनर लगता है। इसके बावजूद ग्राहक प्लास्टिक के सस्ते सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे पीढ़ियों से इस पुश्तैनी कारीगरी के सहारे परिवार पाल रहे लोगों की आमदनी प्रभावित हो रही है। मेले में दुकानें लगाने वाले हस्तशिल्पियों को उम्मीद थी कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक उनके उत्पाद खरीदेंगे, लेकिन इस बार बिक्री काफी कम रही। लकड़ी और लोहे से तैयार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का कारोबार विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। बजौरा के कारोबारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से कुल्लू दशहरा में पारंपरिक वस्तुओं की दुकान लगा रहे हैं। हर वर्ष बेहतर उत्पाद लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कारोबार उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लकड़ी के उत्पाद टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होने के बावजूद लोग कम कीमत के कारण प्लास्टिक का सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार ने कहा कि पारंपरिक हस्तशिल्प केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि हिमाचल की संस्कृति और विरासत की पहचान भी है। यदि इनकी मांग घटती रही, तो आने वाली पीढ़ियों तक यह हुनर पहुंचाना मुश्किल होगा। उन्होंने लोगों से स्थानीय कारीगरों के उत्पाद खरीदने की अपील की, ताकि पारंपरिक कला को संरक्षण मिलने के साथ हस्तशिल्पी परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके।



बिलासपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के अलावा घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में भी लगेगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद और मोटर वाहन चालान सहित लंबित एवं पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति न्यायालय में लंबित नहीं होने वाले विवाद भी लोक अदालत में रख सकते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है।

तृसा स्कूल चलवाड़ा में धूमधाम से मनाई दीपावली रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा



भारतेन्दु संवाददाता, चलवाड़ा। तृसा पब्लिक स्कूल चलवाड़ा में दीपावली के उपलक्ष्य पर रंगोली, दीया और कैंडल मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इसमें विद्यालय के चारों सदनों रोज, डेजी, लोटस और लिली के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा से विद्यालय परिसर को रंग-बिरंगी रंगोलियों और आकर्षक कलाकृतियों से सजाया। जूनियर विंग की रंगोली प्रतियोगिता में डेजी और लोटस सदन ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया, जबकि रोज और लिली सदन दूसरे स्थान पर रहे। दीया एवं कैंडल मेकिंग प्रतियोगिता में डेज़ी सदन प्रथम रहा। सीनियर विंग की रंगोली प्रतियोगिता में डजी और लिली सदन संयुक्त रूप से प्रथम, लोटस सदन द्वितीय और रोज सदन तृतीय स्थान पर रहा। दीया एवं कैंडल मेकिंग प्रतियोगिता में रोज सदन ने दूसरा तथा लिली और लोटस सदन ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल ने सभी प्रतिभागियों की कलाकृतियों का बारीकी से निरीक्षण कर परिणाम घोषित किए। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन वरिंदर नारियल और प्रधानाचार्य राकेश राणा ने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों को मेहनत, रचनात्मकता और लगन के साथ जीवन में आगे बढ़कर विद्यालय और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

32.57 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में अमृतसर से सरगना गिरफ्तार, नूरपुर पुलिस की कार्रवाई जारी

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32.57 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी मामले में अमृतसर, पंजाब से एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार पुत्र दर्शन कुमार निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 4 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर 2026 को सीआईए विंग नूरपुर की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि नागनी माता मंदिर बस स्टॉप, कंडवाल के पास दो युवक चिट्टा बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दोनों की तलाशी ली। इस दौरान राकेश ठाकुर (36) निवासी खनोड़, तहसील धर्मपुर, जिला मंडी, वर्तमान निवासी दाड़नू, धर्मशाला के बैग में रखी जींस की जेब से 32.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मौके पर मौजूद दूसरे आरोपी विकास (24) निवासी बरोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना नूरपुर में 15 अक्टूबर को अभियोग संख्या 260/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ और जांच के आधार पर अमृतसर से तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अब पुलिस नशे की सप्लाई के मूल स्रोत, सप्लायरों और आगे बिक्री से जुड़े लोगों की पहचान के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस ने आम जनता से नशे के अवैध कारोबार की सूचना देने और नशा विरोधी अभियान में सहयोग करने की अपील की है।



लोगों की समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता रहेगा : डीसी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर की नवनियुक्त डीसी किरण भड़ाना ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने और जिले में विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान रहेगा। डीसी ने रेलवे और फोरलेन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करवाने तथा गोबिंद सागर झील सहित जिले के पर्यटन स्थलों की संभावनाओं को विकसित करने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे।

विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें अधिकारी : अमित कुमार शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को बहुउद्देश्यीय भवन में जिला में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर चर्चा की गई।

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं तथा योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत तथा भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने नवगठित पंचायतों की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। सभी नवगठित पंचायतों के लिए फर्नीचर खरीदने को 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डीसी ने ई-परिवार सत्यापन, 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों का पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण तथा समर्थ पोर्टल पर पंचायतों की आय ऑनलाइन दर्ज करने के कार्य में तेजी लाने को कहा।



उन्होंने कम व्यय वाली पंचायतों को उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग करने और लंबित जांच एवं रिकवरी मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश भी दिए। वीबी-जी राम जी योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने और किसी भी पंचायत में शून्य मस्टररोल की स्थिति न रहने देने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बताया गया कि 2012 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इनमें 1344 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 668 निर्माणाधीन हैं। विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत 431 आवासों का निर्माण भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और 18.84 करोड़ रुपए का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया।

सूरजपुर चौक पर बंद दुकान के बरामदे में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। सूरजपुर चौक के पास एक बंद दुकान के बरामदे में करीब 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। स्थानीय लोग उसे 'बाबा' के नाम से जानते थे। बताया जा रहा है कि वह पिछले 2-3 वर्षों से सूरजपुर और मोहटली क्षेत्र में घूमता था तथा भीख मांगकर जीवनयापन करता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने शव का निरीक्षण किया। इस दौरान शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज या मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने भी किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेजा गया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए शव को 72 घंटे तक शवगृह में रखा जाएगा। पुलिस ने पहचान के लिए फोटोग्राफ समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र की आपदा सहायता पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस जनता को दे हिसाब : परमार

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष व सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने पीडीएनए की आर्थिक सहायता को लेकर सुलह कांग्रेस के नेता के बयान पर पलटवार किया है।



उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रभावित हिमाचल को मिली आर्थिक सहायता के लिए कांग्रेस नेताओं को आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वे धन्यवाद देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं, बल्कि कृतज्ञता और जवाबदेही जरूरी है। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदा की घड़ी में हिमाचल के साथ खड़ी रही है। गृह मंत्रालय की ओर से 18 जून, 2025 को जारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1504.80 करोड़ रुपए है। इसकी पहली किस्त के रूप में 451.44 करोड़ रुपए 7 जुलाई, 2025 को जारी किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर, 2025 को हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। ऐसे में केंद्र के योगदान पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस नेताओं को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार दस गारंटियों और बड़े-बड़े वादों के सहारे सत्ता में आई, लेकिन अब अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस नेता बताएं कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितनी महिलाओं को घोषित आर्थिक सहायता का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि, केंद्र के हिस्से और जारी किस्त के बीच अंतर समझना जरूरी है। आधे-अधूरे आंकड़ों से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।

सरकारी नौकरी से स्वरोजगार तक के अवसरों की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल करियर सेंटर मंडी की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मौहीं में भविष्य सेतु कार्यक्रम के तहत करियर काउंसलिंग एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षुओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, स्वरोजगार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने आईटीआई उत्तीर्ण करने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर समय प्रबंधन और निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य विभाग से डॉ. वीर विक्रम सिंह ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरि

अन्निमारी कोर्ते खूबसूरत अंदाज में

अन्निमारी कोर्ते फिनलैंड की प्रमुख 100 मीटर बाधा दौड़ एथलीट हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी तेज गति, तकनीक और बाधाओं को पार करने की क्षमता उन्हें एक प्रतिभाशाली धाविका बनाती है।



स्पोर्ट्स विंडो

यूथ ओलंपिक : 15 साल की तन्वी पात्री बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली। 15 साल की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पात्री यूथ ओलंपिक गेम्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। वे इस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। इसके साथ ही इस इवेंट में भारत का पहला महिला सिंगल्स मेडल भी पक्का हो गया है। तन्वी ने सेमीफाइनल में जापान की दूसरी सीड युज़ुनो वतनाबे को 21-14, 11-21, 21-19 से हराया। तन्वी ने मुकाबले की शुरुआत अच्छी की और पहला गेम 21-14 से अपने नाम किया। हालांकि, वतनाबे ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए 21-11 से जीत हासिल की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। एक समय मुकाबला बराबरी पर था। हालांकि तन्वी ने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा और 21-19 से गेम जीतकर फाइनल में जगह बना ली। तन्वी का मैच चीन की मजबूत यी शिन झांग से है। झांग हाल ही में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। दोनों खिलाड़ी इस साल एशिया जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आमने-सामने आई थीं। तब तन्वी को 18-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा था। यूथ ओलिंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है। एचएस प्रणय ने 2010 में सिंगापुर में हुए पहले यूथ ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद लक्ष्य सेन 2018 में ब्यूनस आयर्स में रनर-अप रहे थे। 2014 में आदित्य जोशी लड़कों के सिंगल्स सेमीफाइनल तक पहुंचे थे।



शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने के बाद पहले ही मुकाबले में हारे अलेक्जेंडर ज्वेरेव

एजेंसी, पेरिस। पुरुष टेनिस में विश्व नंबर एक की कुर्सी संभालने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव का शीर्ष रैंकिंग पर सफर हार के साथ शुरू हुआ। ज्वेरेव को बुधवार को पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में इटली के लोरेंजो मुसेटी के हाथों 6-7, 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार से निराश जर्मनी के ज्वेरेव ने अपनी खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा, 'हां, मैं खराब खेला। पिछले कुछ महीनों में शायद यह मेरे सबसे खराब मुकाबलों में से एक था।' ज्वेरेव के बाद रिकॉर्ड सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के क्वालीफायर खिलाड़ी रिंकी हिजिकाता ने 2-6, 6-3, 6-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। सात बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने अमेरिका के एलेक्स मिशेलसन को 7-6, 6-3 से हराया। लगातार छठी जीत दर्ज करने वाले 23 वर्षीय अल्कराज के सामने अगले दौर में माटेओ बेरेटिनी की चुनौती होगी। दसवीं वरीयता प्राप्त जोकोविच ने हिजिकाता के खिलाफ मुकाबले में अच्छी शुरुआत की और पहले सेट में दबदबा बनाए रखा। हालांकि, दूसरे सेट में 3-3 की बराबरी के बाद वह लगातार तीन गेम गंवा बैठे। तीसरे सेट की शुरुआत में वह अपने सहयोगी स्टाफ पर नाराजगी जताते नजर आए। इसके बाद सातवें गेम में उनकी सर्विस टूट गई। हिजिकाता ने एक बार फिर जोकोविच की सर्विस तोड़ी और उनके बैकहैंड शॉट के कोर्ट से बाहर जाने के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया।



अमेरिकी क्रिकेट को दिवालियापन से निकालने की तैयारी शुरू

एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिका क्रिकेट को दिवालियापन से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट नियुक्त ट्रस्टी मार्क डेनिस ने बोर्ड के लिए तीन स्वतंत्र डायरेक्टर के नाम प्रस्तावित किए हैं। इनमें सेलिना कैंग, पैट्रिक सिंगलटन और नॉर्मन वेन शामिल हैं। नई टीम आईसीसी से निलंबित सदस्यता बहाल कराने और अमेरिकी क्रिकेट में प्रशासनिक स्थिरता लाने की जिम्मेदारी संभालेगी। यह प्रस्ताव इ क्रिकेट के रिऑर्गेनाइजेशन प्लान का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट में दाखिल किया गया है। मेजर लीग क्रिकेट की मालिक कंपनी अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (एसीई) ने भी संगठन को चलाने के लिए 29 करोड़ 68 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग देने का भरोसा दिया है। कोर्ट नियुक्त ट्रस्टी मार्क डेनिस ने 15 जनवरी 2027 के आसपास रिऑर्गेनाइजेशन प्लान की सुनवाई कराने का अनुरोध किया है। यह सुनवाई अधिकतम 22 जनवरी तक हो सकती है। फंडिंग व्यवस्था के लिए 29 जनवरी तक कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। प्लान को मंजूरी मिलने और सभी शर्तें पूरी होने के बाद तीनों नए डायरेक्टर पद संभाल सकते हैं। उसी समय यूएसए क्रिकेट के मौजूदा बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

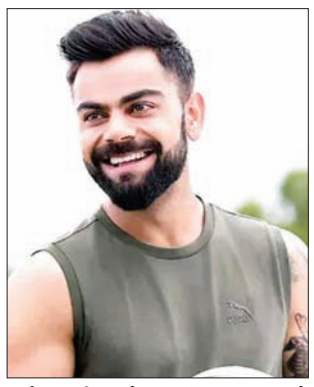
38 साल के हुए 'किंग' कोहली

क्रिकेटरों और कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर दी बधाईयां

एजेंसी, नई दिल्ली

विराट कोहली वीरवार को 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कई क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर बधाईयां दी हैं। इनमें शिखर धवन, रवि शास्त्री, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक भी शामिल हैं। सुरेश रैना ने लिखा कि एक बार का किंग, हमेशा किंग रहता है। वहीं दिनेश कार्तिक ने कोहली के फिटनेस की तारीफ की है। भारत के पूर्व हेड कोच रहे रवि शास्त्री ने खास अंदाज में कोहली को जन्मदिन की बधाई दी है।

शिखर धवन ने कोहली के जुनून और भूख को सराहा



पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके खेल के प्रति जुनून, मेहनत और लगन की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कोहली का खेल के प्रति प्यार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है।

रैना बोले- कोहली को बल्लेबाजी करते देखना खुशी की बात

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोहली को किंग बताते हुए उनके कवर ड्राइव और यादगार रन चेज का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि कोहली ने क्रिकेट फैंस को अनगिनत यादें दी हैं। उन्हें कोहली की बल्लेबाजी देखना बेहद पसंद है।

माया चेन्नई ओपन के क्वार्टर फाइनल में

सानिया मिर्जा के बाद ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी

एजेंसी, चेन्नई

17 साल की माया राजेशवरन रेवती चेन्नई ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वह 14 साल बाद किसी डब्ल्यूटीए टूर-लेवल सिंगल्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2012 में सानिया मिर्जा ने पट्टाया ओपन में यह उपलब्धि हासिल की थी। माया ने बुधवार को राउंड ऑफ-16 में पोलैंड की वेरोनिका फाल्कोवस्का को 6-4, 6-3 से हराया।

भारत का 14 साल का इंतजार हुआ खत्म

माया 2012 में सानिया मिर्जा के बाद डब्ल्यूटीए टूर सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वर्ल्ड नंबर-669 माया ने पोलैंड की क्वालिफायर वेरोनिका फाल्कोवस्का को 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। माया एक समय पहले सेट में 2-4 से पीछे थीं, लेकिन लगातार गेम जीतकर 6-4 से सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में 5-3 की बढ़त बनाने के बाद माया ने तीसरे मैच पॉइंट पर मुकाबला जीत लिया। पिछले दो सीजन में कोई भारतीय खिलाड़ी दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया था। माया ने यह सिलसिला तोड़ा।



दक्षिण कोरिया को 8-1 से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत

हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब-2026 के लिए अब जापान से होगी भिड़ंत

एजेंसी, मोहाली

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी। अब गुरुवार को खिताबी मुकाबले में उसका सामना जापान से होगा।

भारत की जीत में शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह ने दो-दो गोल दागे। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, अंगद बीर सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने एक-एक गोल किया। दक्षिण कोरिया की ओर से एकमात्र गोल हान सांगजुन ने किया। मोहाली के इस स्टेडियम में भारत का यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। घरेलू दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम लीग चरण में अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर अपराजित रही थी और उसने सेमीफाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।



भारत ने चौथे मिनट में शिलानंद के गोल से बढ़त बनाई। हालांकि, नौवें मिनट में हान सांगजुन ने कोरिया को बराबरी दिला दी। इसके तुरंत बाद कप्तान हरमनप्रीत ने पेनाल्टी कॉर्नर पर दमदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को फिर आगे कर दिया। 13वें मिनट में गोलकीपर के बचाव के बाद मिले रिबाउंड पर शिलानंद ने अपना दूसरा गोल दागा। दूसरे क्वार्टर में भारतीय आक्रमण और तेज हो गया। सुखजीत ने 21वें मिनट में शानदार रिवर्स फ्लिक से गोल किया। इसी मिनट दिलप्रीत ने अंगद के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए भारत की बढ़त 5-1 कर दी। 25वें मिनट में हरमनप्रीत के लंबे हवाई पास को नियंत्रित कर दिलप्रीत ने अपना दूसरा गोल किया। मध्यांतर तक भारत 6-1 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में कोरियाई टीम को एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर उतारने के कारण पांच मिनट का येलो कार्ड झेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अंगद ने 36वें मिनट में भारत के लिए सातवां गोल किया। आखिरी क्वार्टर में कोरिया की टीम भारतीय रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रही। 54वें मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास से आठवां गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। दो गोल करने वाले दिलप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने जीत का श्रेय पूरी टीम के सामूहिक प्रयास को देते हुए कहा कि टीम की प्राथमिकता तय रणनीति को मैदान पर लागू करना था। उन्होंने मोहाली में परिवार और प्रशंसकों के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करने को विशेष अनुभव बताया।

जापान ने मलेशिया को 5-3 से हराया

जापान ने पहले सेमीफाइनल में निर्धारित 60 मिनट तक गोलरहित मुकाबले के बाद पेनाल्टी शूटआउट में मलेशिया को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पांचवें-छठे स्थान के मुकाबले में चीन ने बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारत अब पांच नवंबर को शाम सात बजे जापान के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मौजूदा चैंपियन टीम की नजरें छठी बार खिताब जीतकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बादशाहत और मजबूत करने पर होंगी।

त्रिपुरा ने सौराष्ट्र को 133 रन से हराकर दर्ज की पहली जीत



एजेंसी, अगरतला

त्रिपुरा ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए वीरवार को यहां पूर्व चैंपियन सौराष्ट्र को 133 रन से करारी शिकस्त देकर मौजूदा सत्र की पहली जीत दर्ज की। ऑफ स्पिनर संदीप सरकार और तेज गेंदबाज अभिजीत सरकार ने सात विकेट साझा कर त्रिपुरा की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। त्रिपुरा ने 342 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही सौराष्ट्र को 208 रन पर आउट कर अपने क्रिकेट इतिहास की यादगार जीत दर्ज की। इससे पहले टीम ने पिछले वर्षों में एलीट ग्रुप में हिमाचल प्रदेश और गोवा के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी। सौराष्ट्र ने दिन की शुरुआत में सात विकेट पर 131 रन से आगे खेलना शुरू किया। अनुभवी अर्पित वासवदा और चेतन सकारिया की कोशिश टीम को मुश्किल से निकालने की थी, लेकिन दिन के पहले ही ओवर में अभिजीत ने सकारिया को पवेलियन भेजकर सौराष्ट्र की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। इसके बाद वासवदा (89 रन, 189 गेंद) और नील पंड्या (नौ रन, 63 गेंद) ने नौवें विकेट के लिए 59 रन जोड़कर सौराष्ट्र की हार को कुछ देर के लिए टाला। अभिजीत ने पंड्या को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। वासवदा ने 122 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए एक छोर संभाले रखा। वह त्रिपुरा के कप्तान मणिशंकर मुरासिंह के सटीक थ्रो रन आउट हुए जिससे सैराष्ट्र की पारी समाप्त हो गयी। चार मुकाबलों में यह त्रिपुरा की पहली जीत है। इस सफलता के साथ टीम छह अंक लेकर अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ पारी की बड़ी हार झेलने के बाद पूर्व चैंपियन जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देना त्रिपुरा की उपलब्धि को और खास बनाता है।

ब्रिटिश पर्यटकों को भारत बुलाएगी एयर इंडिया

वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की पहचान मजबूत करने के लिए नई पहल

एजेंसी, नई दिल्ली

टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और देश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से नई पहल की है। इसके तहत कंपनी ने बुधवार को लंदन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ब्रिटेन की प्रमुख पर्यटन एवं ट्रैवल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के दौरान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की विभिन्न संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया गया।

प्राकृतिक स्थलों की वैश्विक पहचान बढ़ाने की तैयारी



फाइल फोटो

कंपनी ने विदेशी यात्रियों को भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक स्थलों और अनूठे पर्यटन अनुभवों से परिचित कराने का प्रयास किया। भारत में हिमालयी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तटों, ऐतिहासिक शहरों और धार्मिक स्थलों तक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर विदेशी पर्यटकों को भारत की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारत में पर्यटन बढ़ाने को ट्रैवल कंपनियों के साथ मंथन

कार्यक्रम में साउथहॉल ट्रैवल, ब्राइटसन ट्रैवल, मोरेसैंड, स्काईलॉर्ड ट्रैवल्स, कार्लटन लीज़र, टीयूआई, ट्रेलफाइंडर्स, कुओनी, एक्सपीडिया, ट्रिप डॉट कॉम और अकबर ट्रैवल्स सहित कई प्रमुख ट्रैवल कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा लंदन गैटविक एयरपोर्ट के प्रतिनिधि भी आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थलों की जानकारी बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की संभावनाओं को सामने लाने पर चर्चा की गई। एयर इंडिया ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर देश की पर्यटन पहचान को मजबूत करना है।

रीयल मैड्रिड ने आखिरी क्षणों में एईके एथेंस को हराया

फेडेरिको वाल्वरडे के निर्णायक गोल की बदौलत 3-2 से हासिल की जीत

एजेंसी, मैड्रिड

फेडेरिको वाल्वरडे के निर्णायक गोल की बदौलत रीयल मैड्रिड ने यूईएफए चैंपियंस लीग में एक बार फिर आखिरी क्षणों में बाजी पलटते हुए बुधवार को एईके एथेंस को 3-2 से हराया। लीवरपूल को रोमांचक मुकाबले में फेनरबाशे के हाथों 2-3 से चौकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर सिटी ने भी दो बार बढ़त गंवाने के बाद आरबी लाइपजिग को इसी अंतर से 3-2 से हराया। तो वहीं कोमो ने लेंस को 9-1 से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की। पिछले सत्र की उपविजेता आर्सेनल ने स्लाविया प्राग को 2-1 से शिकस्त दी।

रिकॉर्ड 15 बार की यूरोपीय चैंपियन रीयल मैड्रिड लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के साथ इस सत्र में चार मैचों के बाद शत-प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड कायम रखने वाली दूसरी टीम बन गई। मैड्रिड को ऑल्विन एरिना में एईके एथेंस के खिलाफ दो बार पिछड़ना पड़ा, लेकिन वाल्वरडे ने 92वें मिनट में लंबी दूरी से शानदार गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। मैड्रिड ने पिछले महीने रोमा के खिलाफ भी आखिरी समय में 4-3 से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में टीम ने अंतिम 10 मिनट में तीन गोल किए थे । एईके की ओर से अबूबाकरी कोइटा ने पहले हाफ में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। जूड बेलिंघम ने बैकहील से गोल कर मैड्रिड को बराबरी दिला दी।



मैच के 75वें मिनट में स्तावरोस पिलियोस ने मेजबान टीम को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन तीन मिनट बाद ही किलियन एमबापे ने स्कोर बराबर कर दिया।

इसके बाद एमबापे का एक शॉट क्रॉसबार से टकराया, जबकि वाल्वरडे ने इंजरी टाइम में निर्णायक गोल कर दिया। लीवरपूल ने फेनरबाशे के खिलाफ दोनों हाफ में बढ़त बनाई, लेकिन उसे बरकरार रखने में नाकाम रहा। अंततः उसे इस सत्र की चैंपियंस लीग में पहली हार का सामना करना पड़ा।

कपास आयात पर कस्टम ड्यूटी छूट 31 दिसंबर तक बढ़ी

एजेंसी, नई दिल्ली। देश के कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कपास (कॉटन) के आयात पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट की अवधि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में विशेष और उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे स्पिनिंग मिलों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कम लागत पर कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। सरकार के इस कदम से उत्पादन लागत कम करने और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब भारतीय कपड़ा निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में देश का कुल कपड़ा निर्यात सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत बढ़कर 29,776 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, अप्रैल से अगस्त की अवधि में यह आंकड़ा 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। कॉटन यार्न, फैब्रिक और हैंडलूम उत्पादों के निर्यात में भी 24 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि कच्चे माल की उपलब्धता और निर्यात को मिलने वाले प्रोत्साहन से उद्योग का विस्तार होगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ा उत्पादों की स्थिति और मजबूत हो सकती है।



ट्राई के नए नियमों से सुधरेगी कॉल क्वालिटी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के टेलीकॉम नेटवर्क को आधुनिक बनाने और कॉल गुणवत्ता में सुधार के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत 'टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026' एक जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को पुराने नेटवर्क सिस्टम की जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित इंटरकनेक्शन तकनीक अपनानी होगी। साथ ही लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (एलएसए) स्तर पर नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना अनिवार्य होगा। संशोधित नियमों में कंपनियों को अनावश्यक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) स्वेच्छा से सरेंडर करने की छूट दी गई है। इससे उनके बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च कम होगा। इसके अलावा बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन की अवधि छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। भुगतान में देरी पर ब्याज दरों की सीमा और नियमों का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड का प्रावधान भी किया गया है। ट्राई के इस कदम से मोबाइल उपभोक्ताओं को बेहतर और विश्वसनीय वॉयस कॉलिंग सुविधा मिलने की उम्मीद है। नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन आसान होने से कॉल ड्रॉप की समस्या कम करने और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।

खनन क्षेत्र की संभावनाओं पर गोवा में जुटे विभिन्न राज्यों के मंत्री

गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, दो दिन तक होगा मंथन

एजेंसी, गोवा

केंद्रीय खान मंत्रालय के तत्वावधान में राज्यों के खान मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार को गोवा में शुरू हुआ। दो दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के खान मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य देश के खनन क्षेत्र की प्रगति, संभावनाओं और चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श करना तथा इसके विकास और विस्तार के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना है।

खान मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह सम्मेलन राज्यों के खान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराएगा। इसमें खनन उद्योग की मौजूदा स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही खनन गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने और उद्योग के विस्तार के लिए जरूरी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
सत्यमेव जयते

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत होगा समन्वय

सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव, सफल पहल और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय का मानना है कि अलग-अलग राज्यों के अनुभवों से खनन क्षेत्र के विकास के लिए नई संभावनाएं सामने आएंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद मजबूत होता है।